



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 67]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 1990/फाल्गुन 28, 1911

No. 67]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 1990/PHALGUNA 28, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

बजट प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1990

वित्त मंत्रालय (आ. का. वि.) यू० . ओ. सं.  
591/अ. सं. (बजट)/90—निम्नलिखित को सर्वसाधारण  
की सूचना हेतु प्रकाशित किया गया :—

बजट 1990-91

वित्त मंत्री—

प्रो. मधु दंडवते

का भाषण

19 मार्च, 1990

का भाषण

19 मार्च, 1990

“भाग” “क”

माननीय अध्यक्ष,

1. इस नई सरकार का पहला बजट पेश करने का अवसर  
मिलने पर मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ।

2. लगभग 100 दिन पहले देश में राजनीतिक परिवर्तन  
की एक लहर आई थी। नई सरकार ने, जिसे, राजनीतिक  
सम्बद्धताओं को परे रखते हुए इस आदरणीय सदन का एक  
शानदार विश्वास प्राप्त हुआ था, लोगों से इसे प्राप्त जनादेश  
का सम्मान करने व उस पर अमल करने का वादा किया  
था।

3. प्रारम्भ में, मैं उस आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ  
कहना चाहूंगा जो हमें पिछली सरकार के विरासत से प्राप्त  
हुई है। ऐसा मैं किसी कटुता की भावना से नहीं कह रहा हूँ  
बल्कि सदन को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ।  
1 दिसम्बर, 1989 को केन्द्रीय सरकार का बजटीय घाटा 13,790  
करोड़ रुपए था, जो 1989-90 के बजट में पूरे वर्ष के लिए  
पूरेनुमानित घाटे से लगभग दुगना है। वित्तीय वर्ष शुरू  
होने के बाद से थोक कीमतों में 6.6 प्रतिशत की  
वृद्धि हुई है। भुगतान संतुलन की स्थिति बड़े दबाव  
में थी और विदेशी मुद्रा भण्डार (स्वर्ण तथा एस. डी.

आर. को छोड़कर) कम होकर लगभग 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे। खाद्यान्न भण्डार कम होकर 110 लाख मी. टन रह गया था।

4. अभी केवल कुछ दिन पहले सभापटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में वर्तमान आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में सामान्य रूप से चर्चा की गई है। में व्यौरों की चर्चा नहीं करूंगा बल्कि केवल कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालूंगा।

5. वर्ष 1989-90 में विकास दर में कुछ कमी आई है। सकल घरेलू उत्पाद में 4 से 4.5 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में लगभग 6 प्रतिशत और कृषि उत्पादन में पिछले वर्ष प्राप्त किए गए शिखर स्तर से 1 प्रतिशत अथवा इसके लगभग वृद्धि होने का अनुमान है।

6. इस वर्ष मूल्य वृद्धि से बहुत सी वस्तुओं के समूहों पर प्रभाव पड़ा है तथा मुद्रास्फीति के दबाव का राजकोषीय असंतुलन के साथ एक स्पष्ट संबंध है। बजटीय घाटा तथा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि लक्ष्य से अधिक ही रही है। 1989-90 के संशोधित अनुमानों से, जिन्हें मैं कुछ देर बाद प्रस्तुत करूंगा, पता चलता है कि बजटीय घाटा, वर्ष 1989-90 के लिए बजट अनुमानों में पूर्वानुमानित 7,337 करोड़ रुपए से काफी अधिक रहने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष के शुरू होने से लेकर 23 फरवरी 1990 तक कुल मौद्रिक संसाधनों की वृद्धि दर 16.5 प्रतिशत थी।

7. जहां तक इस वर्ष व्यापार निष्पादन का संबंध है, वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान रुपयों की दृष्टि से निर्यात में 38 प्रतिशत और आयात में 21 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। परन्तु मुद्रा भण्डारों पर दबाव बना हुआ है क्योंकि व्यापार निष्पादन में हुआ मुधार इतना नहीं है जिससे कि ऋण-परिशोधन दायित्वों में वृद्धि प्रतिसंतुलित हो सके।

8. मैंने इन बातों का जिक्र इसलिए किया है जिससे कि उन दबावों का पता चल सके जिनके अन्तर्गत नई सरकार को अपने जनादेश की पूर्ति करने के उपाय और साधन खोजने हैं।

9. नई सरकार का पहला काम कीमतों में वृद्धि को रोकना है। कीमतों के संबंध में एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई थी और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करने, मुद्रास्फीतिकारी मनोवृत्ति को समाप्त करने तथा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए गए थे। किन्तु कीमत संबंधी स्थिति अब भी चिन्ता का विषय बनी हुई है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना इस सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है।

10. मूल्य स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से खाद्यान्नों का पर्याप्त भण्डार होना बहुत जरूरी है। सरकार ने, वसूली संबंधी प्रयासों को तेज करने और भण्डारों के पुनर्निर्माण के काम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। परिणामतः चावल की वसूली पहले ही लगभग 100 लाख मी. टन के नए शिखर स्तर पर पहुंच गई है। है। केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्न भण्डारों में वृद्धि की गई है और ये भण्डार फरवरी के प्रारम्भ में 116.7 लाख मी. टन थे, जबकि पिछले वर्ष इसी समय ये भण्डार 83.4 लाख मी. टन के थे। अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तेज करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के खुले बाजार मूल्यों को स्थिर रखने के लिये बाजार में हस्ताक्षेप किया जा रहा है।

11. एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या जो इस समय देश के सम्मुख है, वह हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति पर दबाव के संबंध में है पिछले कुछ वर्षों के दौरान व्यापार के बड़े और चालू खाते के घाटों को विदेशी मुद्रा भण्डारों को कम करने तथा विदेशी उधारों की मात्रा में वृद्धि करके पूरा किया गया है। भुगतान संतुलन पर दबावों से निबटने तथा आठवीं योजना अवधि के दौरान एक सक्षम स्थिति सुनिश्चित करने की दृष्टि से, निर्यात को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अपनी अनिवार्य आयात संबंधी जरूरतों के वित्त पोषण के लिए अधिक मात्रा में विदेशों से उधार लेने के विकल्प से हमारी परिश्रम से अर्जित आर्थिक आजादी खतरे में पड़ सकती है इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, 1.4.1990 को घोषित की जाने वाली 1990-93 की अवधि के संबंध में आयात-निर्यात नीति में निर्यात को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और ऐसे निर्यात को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे अधिक मात्रा में निवल विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। हमारी औद्योगिक नीति में भी निर्यातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और बाद में मैं निर्यात उत्पादन को प्रोत्साहित करने के संबंध में कुछ राजकोषीय उपायों का उल्लेख करूंगा।

12. थोक वस्तुओं के संबंध में हमारे आयात का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, पिछले कुछ समय से तेल की खपत में लगभग 8 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हो रही है। इससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। पिछले पांच वर्षों में भारत पर विदेशी ऋण दोगुना हो गया है। इससे हमारी स्थिति और भी ज्यादा नाजुक हो गई है। इस प्रवृत्ति को बदला जाना है। मुझे विश्वास है कि अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता और आत्म-निर्भरता की भावना को बनाए रखने के लिए हमारे लोग कोई भी वलिदान करने और किसी भी चुनौती का सामना करने को

तैयार रहेंगे। अधिक विदेशी उधारों से बचने के लिए हम किराया बरतने और कोई भी कठिनाई सहने के लिए तैयार हैं।

13. मुद्रास्फीति और भुगतान संतुलन की कठिन स्थिति की दोहरी समस्या का प्रमुख कारण राजकोषीय असंतुलन है। हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य जिसे प्राप्त किया जाना था, घाटे की अर्थ-व्यवस्था थी। यद्यपि, सातवीं योजना अवधि के दौरान पूर्वानुमानित घाटा 14,000 करोड़ रुपए था, तथापि वास्तविक दृष्टि से यह दुगने से भी अधिक था।

14. घाटे पर काबू पाने के लिए हमें व्यय में वृद्धि को रोकना होगा। मैं सदन को आश्चस्त करना चाहता हूँ कि हम प्रशासनिक खर्च के बोझ को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परन्तु खर्च में कमी करने के लिए सार्वजनिक खर्च के कुछ अन्य क्षेत्रों के विषय में भी ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है, जिनमें अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष सब्सिडी सम्मिलित है। हमें यह देखना होगा कि क्या ये सब्सिडियाँ वस्तुतः उन लोगों तक पहुँच रही हैं जिनके लिए ये निर्धारित की गई हैं अथवा क्या यह लाभ प्रदान करने का कोई और उत्तम तरीका है।

15. राजस्व पक्ष के संबंध में वास्तविक प्रश्न कर अनुपालन का है। कर अपवंचन सर्वत्र विद्यमान है। इससे काले धन की उत्पत्ति होती है, और इसके अर्थ-व्यवस्था पर अन्य गम्भीर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं जैसे कि मुद्रास्फीति तथा फिजूलखर्ची में और वृद्धि होना। अभावों, कृत्रिम रूप से निर्धारित कीमतों और विस्तृत भौतिक नियंत्रणों के फल-स्वरूप भी काले धन का निर्माण होता है। सार्वजनिक व्यय कार्यक्रमों से होने वाले 'रिसावों' से भी हमारे समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना में गम्भीर विकृतियाँ आती हैं।

16. हम काले धन के विस्तार के विरुद्ध, जो एक सामाजिक बुराई तथा आर्थिक अपराध है, एक सतत व बहुमुखी अभियान छेड़ेंगे। कर अनुपालन में सुधार करने की दृष्टि से, हम समुचित कर दरों और सरल कर कानूनों को एक प्रभावशाली कर प्रशासन और अपवंचन के विरुद्ध कठोर अवरोधकों के साथ मिलाएंगे। राजस्व विभाग को हिदायतें दी जा रही हैं कि वह अनुचित साधनों से प्राप्त धन के अशिष्ट प्रदर्शन पर, विशेष रूप से विवाहोत्सवों जैसे अवसरों पर धन के अशिष्ट प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दें। हम उन तत्वों के साथ सख्ती से निपटेंगे जो हमारे कानूनों की अवहेलना करके और राष्ट्र के दुर्लभ संसाधनों का अपव्यय करके अपने आडम्बर और धन शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कर अपवंचकों तथा काले धन के जमाकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई को समन्वित करने की दृष्टि से आर्थिक आसूचना ब्यूरो का पुनर्गठन किया जा रहा है। 'बेनामी' लेन-देनों संबंधी अधिनियम में संशोधन करना होगा ताकि आर्थिक अपराधियों के लिए 'बेनामी' रूप में धन का संग्रह करना कठिन हो जाए।

17. काले धन के विरुद्ध प्रशासनिक नियंत्रणों को आर्थिक उपायों द्वारा समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। हमें विभेदकारी शक्तियों के क्षेत्र को कम करना होगा, जो काले धन को आधार प्रदान करते हैं। हमारी आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत, सामान्यतः, अभेदमूलक, राजकोषीय तथा वित्तीय साधनों पर अधिक बल दिया जाएगा और तदर्थ विभेदकारी भौतिक नियंत्रणों की भूमिका को कम किया जाएगा।

18. मुझे, काले धन को निकालने के लिए प्रोत्साहन स्कीमों और उसका वांछित दिशाओं में उपयोग करने के संबंध में माननीय सदस्यों और राजकोषीय विशेषज्ञों से भी कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। ऐसी स्कीमों का एक लाभ यह बताया गया है कि बेहिसाबी धन का उपयोग तड़क-भड़क पर या उसे अनुत्पादक निवेश के लिए करने की बजाए रोजगार उत्पन्न करने अथवा किन्हीं अन्य सामाजिक दृष्टि से उपयोगी प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। इनकी एक हानि यह है कि इन स्कीमों के अन्तर्गत काले धन के लिए, सामान्यतः निर्धारित दरों की तुलना में, सामान्यतः और अधिक रियायती कर व्यवहार बरतने की व्यवस्था की गई है। विगत में जिन भिन्न-भिन्न स्कीमों का परीक्षण किया गया उनका कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ बल्कि उनका कुछ दुरुपयोग किया गया। मानव चतुराई में बड़ी विचित्र बातें अतर्निहित हैं। विगत में, एक प्रवृत्ति, काले धन को बाहर निकालने के लिए एक श्लाघ्य उद्देश्य से जारी किए गए बाह्य बांडों को एक वैकल्पिक करों की रूप में बदलने में देखने को मिली, जिन्हें प्रीमियम पर अदला-बदला गया इस प्रकार काले धन को सफेद धन में बदलने का एक साधन स्वयं ही सफेद धन को काले धन में बदलने का साधन बन गया।

19. इसके अतिरिक्त, वर्तमान स्थिति में, जबकि हमारी आवश्यकताएं अधिक हैं और संसाधनों की तंगी है, सम्भवतः एक समयबद्ध स्कीम शुरू करने की आवश्यकता है, जिसके अन्तर्गत अधोषित आय और छिपे हुए धन का उपयोग एक अथवा अनेक सामाजिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि मलिन बस्तियों का सुधार, निम्न तथा मध्यम आय वाले वर्गों के लिए मकानों का निर्माण और ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में विशिष्ट कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना करना। कुछेक स्थितियों को छोड़कर, इस स्कीम के अन्तर्गत अधोषित किए गए धन के स्रोतों के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी आय पर एक उचित समान दर पर कर लगेगा।

20. इस प्रकार की कोई स्कीम प्रारंभ करने से पहले सरकार चाहेगी कि उस पर संसद में विस्तृत रूप से चर्चा हो। मैं, बजट चर्चा के दौरान आदरणीय सदस्यों के विचारों का स्वागत करूंगा। इन चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई अन्तिम निर्णय लेगी।

21. देश में सोने का व्यापार सन् 1963 में लागू स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सोने की मांग पर नियंत्रण रखना है। अधिनियम मोटे तौर पर अप्रभावी रहा है। इससे छोटे स्वर्णकारों को कुछ कठिनाई व परेशानी भी हुई है। ऐसे अप्रभावी कानून को जारी रखना व्यर्थ है। इसलिए सरकार का प्रस्ताव स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को समाप्त करने का है। इससे देश के बहुत स शिल्पकारों और छोटे स्वर्णकारों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही हम सीमाशुल्क कानून का उपयोग सोने की तस्करी को रोकने के लिए अधिक कठोरता के साथ करेंगे।

22. अब मैं दीर्घावधिक विकास से संबंधित कुछ मामलों का उल्लेख करूंगा।

23. विकास की पारम्परिक प्रणाली में, जब कि निम्न-स्तर पर निर्धन लोग विकास के लाभों का बहुत कम हिस्सा पाकर चूपचाप कष्ट उठाते रहते हैं, दूसरी ओर उच्च स्तर पर धनाढ्य लोग वैभव के साथ अलग-थलग रहते हैं और आर्थिक विकास के अधिकांश लाभों पर एकाधिकार बनाए रखते हैं। नई सरकार इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करती कि ऊपर वालों के विकास से निचले वर्ग को लाभ प्राप्त हो। इसके स्थान पर, सरकार समानता को बनाए रखते हुए रोजगार संबंधी आयोजना के माध्यम से विकास के लिये कार्य करेगी जिसमें चार स्तम्भों वाले राज्य, जिसे डा. राम मनोहर लोहिया ने "चौखम्बा राज" के रूप में परिभाषित किया था, के विकेन्द्रीकृत संस्थान प्रमुख भूमिका निभायेंगे।

24. हमारी पहली प्राथमिकता रोजगार संबंधी है। नवें दशक में, हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 5 प्रतिशत या उससे थोड़ी अधिक रही है। लेकिन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार लम्बी अवधि से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, जो 1983 में 80 लाख थी, 1987-88 में बढ़कर 120 लाख हो गई। इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी बहुत अधिक है जो अर्द्ध-रोजगार प्राप्त हैं तथा जिन्हें अपने काम से मिलने वाली आय, न्यूनतम सन्तोषजनक आय से काफी कम है। हमारा विश्वास है कि "प्रत्येक नागरिक को उत्पादक और लाभकारी रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है ताकि वह ठीक ढंग से और सम्मान से रह सके"। हम एक रोजगार गारंटी स्कीम शुरू करना चाहते हैं। तथापि, ऐसी स्कीम को देश के सभी भागों में लागू करने के लिये भारी लागत आयेगी तथा इस समय हमारे पास आवश्यक संसाधन नहीं हैं। फिर भी, हमारा प्रस्ताव है कि सूखा-आशंकित क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों, जहां ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या अति विकट है, में रोजगार गारंटी स्कीम की शुरुआत की जाये। वर्ष के दौरान, ग्रामीण विकास विभाग की रोजगार स्कीमों के लिये, आवंटन राशियों में जहां तक सम्भव होगा, वृद्धि की जायेगी।

25. कृषि का तीव्र विकास, हमारी इस नीति का महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। हमने, अच्छी सिंचाई वाले क्षेत्रों में, फसलों के उत्पादन में प्रभावकारी बढ़ोत्तरी प्राप्त की है लेकिन देश के उन काफी बड़े हिस्सों में, जो वर्षा पर निर्भर रहते हैं अथवा कुछ शुष्कता वाले क्षेत्र हैं, पैदावार काफी कम है। कृषि विकास से संबंधित हमारी नीति के अंतर्गत इन क्षेत्रों में सिंचाई, भूमि-विकास, तथा मृदा और नमी के संरक्षण पर पर्याप्त मात्रा में निवेश करके पैदावार बढ़ाने पर ध्यान दिया जायेगा। इन निवेशों से पैदावार में वृद्धि होगी। इससे, कृषि क्षेत्र में और अधिक श्रमिकों को काम मिलेगा। इस प्रयास के समानान्तर, अधिक पैदावार वाले क्षेत्रों में कृषि में विविधता लाने तथा कृषि पर आधारित संसाधन-उद्योगों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। इससे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी क्षेत्रों के विकासशील बाजारों तथा इसके साथ ही संभावित विदेशी बाजारों के बीच आर्थिक सम्पर्क स्थापित होंगे।

26. हमारे देश ने वर्ष 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प को अपनाया था तथा बाद के वर्षों में उसी संकल्प के अनुसार औद्योगिक विकास संबंधी विस्तृत नीतियां बनाई जाती रही हैं। यह आश्चर्य की बात है कि इसी प्रकार का कोई कृषि नीति संबंधी संकल्प नहीं है। यह सरकार इस कमी को दूर करेगी। एक कृषि नीति संकल्प को अपना कर हम कृषि के विकास की प्रारम्भिक बुनियाद रखेंगे। यह एक ऐसे क्षेत्र, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का केन्द्र-बिन्दु है, के प्रति हमारी राष्ट्रीय वचनबद्धता को दर्शायेगा। हम सभी वर्गों के लोगों को इस नीति संकल्प को तैयार करने में सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

27. हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिये वचन-बद्ध हैं कि निवेश योग्य संसाधनों में से 50 प्रतिशत भाग को कृषि विकास और ग्रामीण विकास के लिये लगाया जाये। हमने इन वर्ष की केन्द्रीय आयोजना में इसकी शुरुआत की है जिसके अंतर्गत आयोजना केन्द्रीय संबंधी बजटीय सहायता में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा, जो वर्ष 1989-90 में 44 प्रतिशत था, वर्ष 1990-91 में बढ़कर 49 प्रतिशत हो जायेगा। इसके अतिरिक्त, आयोजना-भिन्न पक्ष के अन्तर्गत, हम ऋण राहत के लिये 1,000 करोड़ रुपये तथा उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के लिये 4,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसका लाभ भी ग्रामीण क्षेत्रों को पहुंचेगा।

28. भूमि सुधार कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिये पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं और आवश्यक संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया जायेगा। इसके साथ ही, भूमि संबंधों की पुनः संरचना के विभिन्न उपायों पर विचार किया जा रहा है और हमें आशा है कि हम राज्य सरकारों के साथ यथोचित रूप से परामर्श करने के पश्चात् इस दिशा में कदम उठावेंगे।

29. पिछले कई वर्षों की अवधि में, निर्धन किसानों, कारीगरों तथा बुनकरों पर ऋण का काफी बोझ बढ़ गया है जिसकी वापसी अदायगी करने में वे असमर्थ हैं। वे ऋण-श्रस्तता और कम आय के एक ऐसे दुश्चक्र में फँस गए हैं जिसके कारण वे निरन्तर निर्धन ही बने रहते हैं। अपने इन किसानों को ऋण के भार से मुक्त कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणा-पत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि 2 अक्टूबर, 1989 की 10,000/- रुपये तक के ऋण वाले किसानों को राहत प्रदान की जायेगी। मुझे सदन को यह बताने हुए हर्ष हो रहा है कि हम किसानों तथा शिल्पकारों को दिए गए वायदे को पूरा करने तथा अपने वचन की पूर्ति करने के लिए अब ऋण राहत को कार्यान्वित करने के लिए तैयार हैं।

30. ऋण राहत प्रदान करने के लिए एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। यह राहत सहायता उन ऋणकर्ताओं के लिये उपलब्ध होगी जिन्होंने सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से 10,000 रुपये तक के ऋण ले रखे हैं। इस राहत में 2 अक्टूबर, 1989 तक की स्थिति के अनुसार, अल्पावधिक दीर्घावधिक ऋणों की, सभी प्रकार की अतिदेय राशियां शामिल होंगी। ऋणकर्ता की ज़ोत-भूमि के क्षेत्र पर कोई सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, उन दोषी ऋणकर्ताओं को, जिन्होंने सक्षम होते हुए भी विगत में ऋणों की वापसी अदायगी करने से जानबूझकर इन्कार कर दिया था, इस स्कीम में शामिल नहीं किया जायेगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऐसे जो ऋण बढ़े खाते डाले जायेंगे, उनके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा समुचित रूप से प्रतिपूर्ति की जायेगी। बहुत से ऐसे व्यक्तियों ने, जिन्होंने दिवालिया होने की याचिकाएं दायर कर दी थी और 10,000 रु. से कम के ऋण ले रखे थे तथा जो 2 अक्टूबर 1989 को अतिदेय थे, उन्हें भी इस स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।

31. राज्य सरकारें भी चाहें तो अपने-अपने सीमा-क्षेत्रों में सरकारी बैंकों के संबंध में ऐसी ही कोई स्कीम आरम्भ कर सकती हैं। संसाधनों की तंगी को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा अपने अधीनस्थ सहकारी ऋण संस्थानों के माध्यम से इसी प्रकार की ऋण राहत स्कीम के कार्यान्वयन हेतु उन्हें सहायता देने संबंधी सुझावों पर विचार करेगी।

32. मेरे विचार से ऋण राहत संबंधी उपाय एक ठोस कदम है जिससे हमारे किसानों, कारीगरों तथा बुनकरों को अपना उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि बैंकिंग प्रणाली की साख में कोई कमी न आये। जब एक बार सभी पिछली अतिदेय राशिओं का हिसाब हो जाये तो यह आशा करना उचित ही होगा कि चालू कार्यों के संबंध में लिये गये ऋणों की वापसी अदायगी ठीक प्रकार से की जाये। इस स्कीम से,

बेहतर कृषि संबंधी वसूलियों तथा जानबूझकर कर दोषी ऋणकर्ताओं जिनसे किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दर्शाई जानी चाहिए, की पहचान करने में सहायता मिलेगी। बैंकों से कहा जा रहा है कि वे एक ऐसी प्रणाली अपनाएं जिसमें इस स्कीम के अन्तर्गत सम्मिलित सभी ऋणकर्ताओं का सही-सही उधार संबंधी विवरण रखा जाये। सरकार यह भी स्पष्ट करना चाहती है कि इस स्कीम की अवधि को न तो बढ़ाया जायेगा और न ही इस स्कीम की पुनरावृत्ति की जायेगी।

33. सरकार कृषि फसलों के मूल्य निर्धारण के लिए उत्पादन की लागतों की संगणना करने के लिए फार्मुले में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करती है ताकि सभी लागतों को पूर्ण रूप से हिसाब में लिया जा सके। फार्मुले में खासतौर से निम्नलिखित बातों को हिसाब में लिया जाएगा :—

- (1) न्यूनतम सांविधिक मजदूरी अथवा, वास्तविक मजदूरी, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर श्रम (पारिवारिक श्रम सहित) का मूल्यांकन।
- (2) किसानों को प्रबन्धकीय और उद्यम संबंधी प्रयासों के लिए पारिश्रमिक।
- (3) मूल्यों की घोषणा और बाजार में फसल के पहुंचने की अवधि के बीच निर्विष्ट लागतों में वृद्धि के लिए वसूली/समर्थन मूल्यों का समायोजन।

नया फार्मुला अगले खरीफ मौसम के लिए घोषित किए जाने वाले वसूली समर्थन मूल्यों में परिलक्षित होगा। चूंकि वसूली मूल्यों को लागतों के अनुरूप संशोधित किया जाता है इसलिए निर्गम मूल्यों के संशोधन से बचना नामुमकिन है। भविष्य में, सरकार वसूली और निर्गम मूल्यों में संशोधन की घोषणा एक ही समय पर करेगी, हालांकि वे अलग-अलग तारीखों से प्रभावी हो सकते हैं।

34. हमारे पर्यावरण के खतरे को और अधिक अनदेखा नहीं किया जा सकता। अनुमान लगाया गया है कि लगभग 1,300 लाख हेक्टेयर भूमि का, भूमि कटाव, लवणता, पेड़ों के आच्छादन की पूर्ण हानि आदि के जरिए अपक्षय हो रहा है। हमारे वनों पर भिन्न-भिन्न प्रकार से दबाव पड़ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में उद्योग, परिवहन और अन्य साधनों से वायु और जल प्रदूषण अत्यधिक है। स्वस्थ पर्यावरण अच्छे जीवन का एक हिस्सा है और उत्पादक पर्यावरण विकास का आधार होता है। ग्रामीण विकास और विकेन्द्रीकरण पर बल देने से हमें संपूर्ण पर्यावरणीय मान्यताओं को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ में मदद मिलेगी।

35. अब मैं गंभीर चिन्ता के एक अन्य क्षेत्र की बात करूंगा, वह है बेरोजगार युवक। हममें से सभी जो अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों का दौरा करते हैं उन्होंने नवयुवकों की दुर्दशा देखी होगी जो कि काम करने में समर्थ हैं और

काम करना चाहते हैं लेकिन वे रोजगार पाने में असमर्थ हैं। इस समस्या का एक दीर्घकालीन हल यह है कि अधिक रोजगार संबंधी विकास नीति अपनायी जाए। परन्तु तत्काल उपाय के रूप में हमने उन उपायों को बढ़ावा देने का निर्णय किया है जो इस देश के युवकों को दक्षताएं प्राप्त करने में मदद देंगे जिससे उनकी लाभप्रद रोजगार के लिए संभावनाएं में सुधार होगा। एक व्यापक व्यवसायिक प्रशिक्षण परियोजना शुरू की गई है जिसमें 28 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। इस परियोजना से शिल्पी प्रशिक्षण, प्रशिक्षण और औद्योगिक कर्मचारियों के उच्च प्रशिक्षण को किस्म में सुधार होगा। हम प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता को जोड़ने का भी प्रस्ताव करते हैं।

36. डा. बी.आर. अम्बेडकर की अनुमति में सन 1956 में अनुसूचित जातियों से संबंधित जातियों से हजारों व्यक्तियों ने बुद्ध धर्म को अपनाया था ताकि वे जाति संबंधी दमन, जिसका वे शताब्दियों से सामना कर रहे हैं, से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तथापि, कट्टरपंथियों की दृष्टि से अनुसूचित जातियों पर लगा सामाजिक कलंक उनके बुद्ध धर्म अपनाने के बाद भी नहीं मिटा। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार जो अनुसूचित जातियों को उपलब्ध थे वे उन्हें केन्द्र सरकार से उनके बुद्ध धर्म अपना लेने के पश्चात् भी उपलब्ध होंगे।

37. कृषि में अधिक श्रमिकों को खपाने की नीति को उद्योग के तेजी से विकास और आधारभूत ढांचे, विशेष रूप से वद्युत और परिवहन, के संतुलित विकास के साथ-साथ चलाया जाना चाहिए। यह स्वतः स्पष्ट है कि कृषि आय में तेजी से वृद्धि और अधिक निवेश तभी कायम रखा जा सकता है यदि निविष्टियों और विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो। यह सरकार एक स्पष्टात्मक और गैर-एकाधिकारिक वातावरण में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए प्राथमिकता देगी। सरकार औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की पुनरीक्षा करेगी और इसे सरल बनाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह लाइसेंसिंग प्रणाली स्पर्धा को रोकने और एक एकाधिकारों को कायम रखने के लिए एक साधन न बन जाए।

38. रोजगार प्रधान और औद्योगिक विकास के लिए किसी भी नीति में खादी, ग्राम और लघु क्षेत्र की विशेष भूमिका होती है, हम कुटीर, लघु और बड़े उद्योगों के सुव्यवस्थित विकास के लिए कार्य करेंगे और बड़े पैमाने द्वारा लघु पैमाने और लघु पैमाने द्वारा कुटीर उद्योगों में अनाधिकार प्रवेश को रोकने के लिए, जहां कहीं भी आवश्यक होगा, संरक्षण प्रदान करेंगे।

39. पिछड़े क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत की केन्द्रीय निवेश संबंधी आर्थिक सहायता हटाने से लघु उद्योगों का विकास प्रभावित हुआ है। हमें अवश्य ही उद्योगों को लोगों के पास ले जाना है और न कि लोगों को उद्योगों के पास। हम, ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में लघु इकाइयों के लिए केन्द्रीय निवेश संबंधी आर्थिक सहायता को पुनः लागू करने का प्रस्ताव करते हैं।

40. लघु उद्योगों को पेश आने वाली एक प्रमुख समस्या, बड़ी इकाइयों द्वारा बिलों के निपटान में देरी की है। उपादान सेवाओं की व्यवस्था करना, जिसमें मध्य-वर्ती द्वारा बिल के नकदीकरण का कार्य किया जाता है, इस देरी को कम करने का एक तरीका है। सदन को यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही कुछ उपाय किए जा चुके हैं।

41. कुटीर और लघु उद्योग क्षेत्र में महिला उद्यमियों की समस्याएं हमारे लिए विशेष रूप से चिन्ता का विषय है। महिला उद्यमियों के लिए माजिन धन और प्रारम्भिक पूंजी से संबंधित व्यवस्थाओं की पुनः जांच की जाएगी और उन्हें उदार बनाया जाएगा।

42. राज्य वित्तीय निगमों द्वारा लघु क्षेत्र में परियोजनाओं को कार्यशील पूंजी के साथ-साथ सावधि सहायता देने के लिए एक एकल द्वार योजना है। इस व्यवस्था से बैंकों से कार्यशील पूंजी की सीमा को अंतिम रूप दिए जाने की प्रतीक्षा किए बिना लघु इकाइयों की स्थापना में सुविधा मिलती है। ऐसे मिश्रित ऋणों के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु परियोजना लागत की वर्तमान सीमाओं को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जा रहा है।

43. रिजर्व बैंक ने ऋण प्रदान करने और सक्षम लघु इकाइयों के पुनर्वास के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों का उद्देश्य लघु क्षेत्र की मदद करना है और न कि इसके रास्ते में अड़चनें डालना है। बैंकों से इन्हें निष्ठापूर्वक लागू करने का अनुरोध किया गया है।

44. हमारे देश के विकास में सरकारी क्षेत्र का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र ने, हमारे देश में औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय विकास के आधार को विस्तृत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। इस वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के समग्र कार्य संबंधी परिणामों से निवल लाभ में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जो पहले वर्ष के 694 करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष 1,103 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 1990-91 में, केन्द्रीय क्षेत्र के उद्यम अपने योजना संबंधी निवेशों के 46 प्रतिशत भाग का वित्तपोषण आंतरिक संसाधनों से करेंगे। हम सरकारी क्षेत्र को और अधिक कार्यकुशल और अच्छे परिणाम देने

वाला क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह और अधिक अधिशेष धनराशियाँ पैदा कर सके जिन्हें फिर से विकास कार्यों में लगाया जा सके।

45. सरकारी उद्यमों की स्थिति इनके कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और प्रबन्ध में उनकी पूर्ण भागीदारी पर अत्यधिक निर्भर करती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि या तो स्टॉक विकल्प की स्कीमों के जरिए अथवा कामगारों को अथवा कामगारों के स्वामित्व वाले न्यासों को शेयरों की बिक्री के जरिए कामगारों को स्वामित्व में हिस्सा दिया जाए। चूंकि सरकारी उद्यमों के इक्विटी शेयरों की बोली बाजार में नहीं लगती इसलिए ऐसे कामगारों के शेयरों के बिक्री और खरीद मूल्यों को तय करने के लिए व्यवस्था तैयार करनी होगी। मैं इस विचार के गुण-दोषों और इसे कैसे लागू किया जा सकता है, के संबंध में माननीय सदस्यों के सुझाव आमंत्रित करता हूँ।

46. हम पूंजी बाजारों के स्वस्थ विकास और सरकारी वित्तीय संस्थानों की भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए भी बचनबद्ध हैं। इन संस्थानों को कार्य संबंधी स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। तथापि, उन्हें अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी भी होनी चाहिए। ये संस्थान कंपनियों के विवादों में और गुप्त रूप से कंपनियों के अधिग्रहण में हिस्सा नहीं लेंगे। सरकार एक ऐसा वातावरण और माहौल पैदा करना चाहेगी जिसमें वित्तीय संस्थान यथार्थवादी ढंग से बिना किसी भय अथवा पक्षपात के अपना कार्य कर सकें।

47. वित्तीय संस्थानों द्वारा पूंजी बाजार में हस्तक्षेप करने संबंधी उनकी भूमिका के बारे में कुछ चिंता व्यक्त की गई है। मैंने इन संस्थानों से उचित मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के लिए कहा है ताकि उनके कार्यकलाप न केवल वस्तु-परक हों अपितु वे ऐसे दिखाई भी दें। प्रत्येक वित्तीय संस्थान से आशा की जाती है कि वह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने जमाकर्ताओं और निवेशकर्ताओं के हित में कार्य करे। कई बार ऐसे अवसर आ सकते हैं जब सम्मिलित तेज-डिया अथवा मंदडिया दबावों के कारण शेयर मूल्यों में असा-मान्य और निरन्तर उतार-चढ़ाव आ जाए। ऐसी स्थितियों में, वित्तीय संस्थाएँ पूंजी बाजार को स्थिरता प्रदान करने की भूमिका निभायेंगी।

48. राष्ट्रीयकरण के पश्चात् से बैंकों के कामकाज में वृद्धि उल्लेखनीय रही है। बैंक सेवा प्रणाली देश के दूर-दराज के इलाकों में भी पहुंच गई है। लोगों की बचत राशियों को एकत्रित करने और उन राशियों को लाभकारी क्षेत्रों तक पहुंचाने के कार्य में बैंक अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीयकरण के समय, कृषि, ग्रामीण विकास और लघु उद्योगों और व्यापार जैसे प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों के लिये बैंक उधार का मात्र 14 प्रतिशत हिस्सा ही प्रदान किया जाता

था। अब, यह हिस्सा बढ़कर लगभग 45 प्रतिशत हो गया है। इससे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सफलता का अनुमान लगाया जा सकता है।

49. बैंक कार्यचालन का एक पक्ष ऐसा भी है जिससे मुझे चिंता होती है। यह कुछ क्षेत्रों में निम्न उधार-जमा अनुपात से संबंधित है। इस अनुपात का निर्धारण कई घटकों द्वारा होता है। मैंने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि वह इस समस्या पर विशेष ध्यान दे तथा वित्तीय नियमों के अनुरूप ऐसे क्षेत्रों में उधार के भुगतान में और सुधार लाए।

50. हमारे बैंकों के प्रबंधक और कर्मचारी, एक समूह के रूप में, सर्वाधिक अर्हताप्राप्त कर्तव्यनिष्ठ तथा कड़ा परिश्रम करने वाले हैं। लेकिन, इसके साथ ही यह भी एक सच्चाई है कि बैंक सेवाओं के संबंध में जनता में उतना संतोष नहीं है जितना कि होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में शायद कुछ संरचनात्मक स्थिरताएं पैदा हो गई हैं। इन स्थिरताओं को दूर किए जाने की आवश्यकता है। बैंक सेवाओं के संबंध में और अधिक प्रतिस्पर्धा और कार्यचालन संबंधी लचीलेपन की आवश्यकता है। बैंक सेवा व्यवस्था को लोगों की जरूरतों के और अधिक अनुकूल बनाना होगा। मैं भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध कर रहा हूँ कि वह बैंकों, बैंक कर्मचारियों, जमाकर्ताओं तथा ऋणकर्ताओं की एक समिति गठित करे जो इन पहलुओं पर विचार करके सरकार को इस बारे में सिफारिशें करे।

51. पिछली सरकार ने वर्ष 1987 में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड के गठन की घोषणा की थी। तीन वर्ष बीत चुके हैं और इस बोर्ड को सांविधिक प्राधिकार प्रदान करने के लिये कोई कानून प्रस्तुत नहीं किया गया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य इस बजट सत्र में पूरा कर दिया जाये।

52. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का मुख्य आधार है। हम कृषि, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैयार की गई क्षमताओं पर गर्व करते हैं। हमारा ध्येय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की प्रतिभा का निम्न-लिखित दो प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का होगा :

—कृषि, गैर-परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य रोजगार सघन गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास।

—आधुनिक प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्म-निर्भरता के सुदृढ़ आधार की स्थापना।

निजी अनुसंधान प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देशीय प्रौद्योगिकियों और नीतियों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन, अनुसंधान और विकास पर सरकारी खर्च, इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

53. विदेश में बसे भारतीयों की संख्या काफी अधिक है। उन्होंने अपने चुने हुए व्यवसायों और कामकाज में जबरदस्त सफलता प्राप्त की है। हमारी प्राचीन संस्कृति की समृद्ध परंपरा के अनुरूप उनकी वास्तविक अवस्थिति ने सुदृढ़ बौद्धिक, दार्शनिक और सामाजिक संबंधों को, जो कि उनके मूल देश में हैं, कमजोर नहीं किया है। सरकार देश में उनकी बचतों के निवेश के लिए उनको दी जा रही विशेष सुविधाओं को जारी रखेगी। प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा ताकि वे विश्वासपूर्वक और घोषित राष्ट्रीय नीति के अनुरूप कार्य कर सकें।

54. अब मैं 1989-90 के संशोधित अनुमानों और 1990-91 के लिए बजट अनुमानों के बारे में कहना चाहूंगा।

वर्ष 1989-90 के लिए संशोधित अनुमान

55. चालू वर्ष के लिए खर्च के संशोधित अनुमान, बजट अनुमानों की तुलना में 5,620 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाते हैं। इसमें से 4,958 करोड़ रुपए आयोजना-भिन्न खाते में, और 662 करोड़ रुपए आयोजना खाते में हैं।

56. आदरणीय सदस्य, हमारे सुरक्षा वातावरण संबंधी दबावों से परिचित हैं, जो दुर्भाग्यवश हमारी अर्थव्यवस्था पर दबावों के साथ-साथ ही हैं। इस प्रकार आयोजना-भिन्न पक्ष में, रक्षा सेवाओं के लिए उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं और प्रतिबद्ध खर्च को पूरा करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जा रही है। उर्वरक सब्सिडी के लिये 950 करोड़ रुपए की और अधिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी जो मुख्यतया अधिक मात्रा में आयात और बकाया दावों के निपटान के कारण हैं। खाद्य सब्सिडी में 276 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है जो मुख्यतया भारतीय खाद्य निगम को देय बकाया राशि के निपटान के लिए है। निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए 468 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। व्याज की अदायगी पर 710 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। सरकार का मत है कि न्यायालय के आदेश के अंतर्गत भोपाल-गैस त्रासदी के पीड़ितों को अदा की जाने वाली हज्जि की राशि उन निर्दोष लोगों की कठिनाइयों की विशालता को ध्यान में रखते हुए बहुत कम है। मामला न्यायालय में समीक्षाधीन है, और इसी बीच सरकार ने पीड़ितों के लिए अंतरिम राहत का भुगतान करने का निर्णय किया है, जिसके वास्ते 320 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो तीन वर्ष की अवधि में बैंक का व्याज मिलाकर 360 करोड़ रुपए बैठेगी। वे वृद्धियां कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से इस संबंध में देनदारी को मंत्रालयों/विभागों के बजट में अंतर्गत करने के परिणामस्वरूप महंगाई भत्ते के लिए की गई एकमुश्त व्यवस्था में बचतों द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हो गई है।

57. प्राप्तियों के अंतर्गत, यद्यपि कंपनी कर और सीमा-शुल्कों से संग्रह, बजट अनुमानों के लगभग ही होने की उम्मीद है। तथापि, संध उत्पाद शुल्कों से प्राप्तियां बजट की तुलना

में 599 करोड़ रुपए कम होने की उम्मीद है, दूसरी और आयकर से संग्रह की राशि 755 करोड़ रुपए अधिक होने की उम्मीद है। कर्गों में राज्यों का हिस्सा, पिछले वर्षों के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित संग्रह-राशि के आंकड़ों के आधार पर 13,232 करोड़ रुपए बैठता है, जबकि बजट में यह राशि 12,438 करोड़ रुपए थी, अर्थात् 794 करोड़ रुपए अधिक। निवल राजस्व प्राप्तियों में कमी, अल्प बचतों, भविष्य निधि संग्रहों और गैरसरकारी भविष्य निधि में विशेष जमा राशियों आदि से होने वाली अधिक प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित हो जाने की उम्मीद है।

58. चालू वर्ष के लिए कुल मिलाकर 11,750 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जबकि बजट में 7,337 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था।

वर्ष 1990-91 के लिए बजट अनुमान

59. अगला वित्तीय वर्ष आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भिक वर्ष है। यह सरकार योजनाबद्ध आर्थिक विकास करने और योजना को लोगों के लिए और अधिक सार्थक बनाने के लिए स्पष्टतः प्रतिबद्ध है। नई नीति के एक भाग के रूप में, अगले वर्ष की आयोजना में हमने उन कार्यक्रमों और स्कीमों के लिए अधिक व्यवस्था की है, जिनसे लोगों को प्रत्यक्षतः लाभ पहुंचता है। हमने उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है, जिनसे अधिक रोजगार का सृजन होता है, स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, हमारे गांवों में रहन-सहन के वातावरण में सुधार होता है और हमारी खेती में सुधार होता है। निर्धनता को दूर करने का यह एक निश्चित मार्ग है। किमानों, वृत्तों और कारीगरों के लिए ऋण-राहत के वास्ते 1,000 करोड़ रुपए की बजट-व्यवस्था को ध्यान में रखे बगैर, कृषि व संबद्ध सेवाओं के लिए पिछले वर्ष के बजट अनुमानों में 31.7 प्रतिशत की वृद्धि की व्यवस्था की जा रही है। गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों संबंधी आवंटन में, जो विभिन्न बजट-शीर्षों में बंटा हुआ है, पिछले वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार कार्यक्रमों के लिए परिव्यय सम्मिलित है, पिछले वर्ष के बजट अनुमानों में 30 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है।

60. हम कृषि और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध हैं और हमारी प्राथमिकताएं तथा कार्यक्रमों इस प्रतिबद्धता के अनुरूप ही हैं।

61. केन्द्रीय योजना 1990-91 के लिए मैं, 39,329 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ—जो चालू वर्ष के परिव्यय की तुलना में 4,883 करोड़ रुपए अथवा 14.2 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 17,344 करोड़ रुपए वजतीय समर्थन के रूप में दिए जायेंगे तथा 21,985 करोड़ रुपए की बकाया राशि, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों और साथ ही उद्योगों के जरिए जुटाई जायेगी।



62. वर्ष 1990-91 के लिए, कृषि और सहकारिता विभाग के वास्ते 905 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है जो चालू वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में 17.5 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त मैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए 155 करोड़ रुपए के परिव्यय का भी प्रस्ताव कर रहा हूँ जबकि 1989-90 में 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी—यह 41 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है।

63. मैंने एक रोजगार गारंटी स्कीम के संबंध में शुरूआत करने के सरकार के इरादे का जिक्र किया है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए प्रस्तावित वार्षिक योजना परिव्यय 3,115 करोड़ रुपए है। मेरा इरादा संसाधनों की सीमाओं के अंदर, कुछ और निधियां प्रदान करने का है ताकि चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार गारंटी स्कीम लागू की जा सके।

64. सरकार, समाज के सर्वाधिक पीड़ित और वंचित वर्गों, अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ समुचित व्यवहार करने के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ है। वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्कीमों के वास्ते 320 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, जबकि 1989-90 के बजट अनुमानों में 269 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। राज्यों की जनजातीय उप-योजनाओं और विशेष घटक योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में भी वृद्धि की गई है।

65. सरकार निरक्षरता उन्मूलन के लिए प्रयासों को तेज करेगी। यह तथ्य निरक्षरता की सीमा का एक स्पष्ट सबूत है कि देश के लाखों मतदाताओं को उम्मीदवारों के नामों का पता मतपत्रों पर उनके चुनाव चिह्नों से लगाना पड़ता है। हमने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए आवंटन में 25 प्रतिशत की वृद्धि की है। सभी स्तरों पर व्यावस्थिक कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में प्राथमिकता वाले और अग्रगो क्षेत्रों को समर्थन दिया जाना जारी रहेगा। मैं वर्ष 1990-91 के दौरान शिक्षा विभाग के लिए 865 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

66. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं के सभी कार्यक्रमों में ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैं वर्ष 1990-91 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वास्ते 950 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

67. सरकार शहरी क्षेत्रों में गरीब, कमजोर और वंचित लोगों के कल्याण को विशेष महत्व देती है। रोजगार प्रदान करने, झाड़ूकर्मों की मुक्ति के लिए कम लागत पर सफाई की व्यवस्था करने तथा रात्रि आश्रय स्थलों के लिए व्यवस्था करने हेतु ठोस प्रयास शुरू करने का प्रस्ताव है। शहरी विकास क्षेत्र के योजना परिव्यय को बढ़ाकर 1990-91 809 GI/90—2

में 272 करोड़ रुपए किया जा रहा है, जबकि 1989-90 के बजट अनुमानों में इस प्रयोजन के लिए 89 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

68. बुनियादी ढांचे संबंधी क्षेत्रों के लिए वर्ष 1990-91 के वास्ते वार्षिक योजना परिव्यय में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए परिव्यय 18.6 प्रतिशत, रेलवे के परिव्यय में 12.4 प्रतिशत तथा विद्युत् क्षेत्र के परिव्यय में लगभग 10 प्रतिशत को वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

69. इन तथा अन्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय योजना परिव्ययों के संबंध में ब्यौरे बजट दस्तावेजों में दिए गए हैं मैं वृहत बजट दस्तावेजों के स्थान पर अपना भाषण देकर इस सदन का समय नहीं लेना चाहता और इस प्रकार सदस्यों को इन दस्तावेजों को पढ़ने की उत्सुकता से वंचित नहीं रखना चाहता हूँ।

70. आदरणीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि अगले वर्ष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि, जिसमें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किये गये योजनागत राजस्व अनुदान भी सम्मिलित हैं, 12,848 करोड़ रुपए होगी, जबकि वर्तमान वर्ष के लिए बजट अनुमानों में की गई सुखे संबंधी सहायता को छोड़कर यह राशि 10,450 करोड़ रुपए है। यह 22.9 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि का द्योतक है।

71. अगले वर्ष के बजट अनुमानों में आयोजना-भिन्न, खर्च के लिए 64,515 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 59,220 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगले वर्ष मुख्य वृद्धि ब्याज अदायगियों की व्यवस्था के अन्तर्गत है जिसके लिए इस वर्ष की 17,710 करोड़ रुपए की राशि की अपेक्षा अगले वर्ष 20,850 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

72. 'एक रैंक एक पेंशन' संबंधी मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट मार्च, 1990 के अंत तक प्राप्त हो जाने की संभावना है तथा सरकार उसके पश्चात् आगे की कार्रवाई करेगी।

73. रक्षा सेवाओं के लिए बजट अनुमानों में 15,750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। रक्षा खर्च में वृद्धि हमारी परिधि से बाहर है। यह हमारी सीमाओं पर स्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम है।

74. स्वतंत्रता संघर्ष अविभाज्य है और इसीलिए यह निर्णय किया गया है कि जिन्होंने पुर्तगाली शासन के विरुद्ध गोआ की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी वे भी केन्द्रीय सरकार के पेंशन व उन अन्य सभी लाभों के हकदार होंगे, जो स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध हैं।

75. नौवें वित्त आयोग ने 1990-95 की अवधि के संबंध में अपनी द्वितीय रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी एक प्रति सिफारिशों के संबंध में सरकार के निर्णयों के विवरण के साथ पिछले सप्ताह सभापत्य पर रख दी गई थी। अगले वर्ष का बजट तैयार करने समय इन्हें ध्यान में रखा गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वित्त आयोग की सिफारिशों से वर्ष 1990-91 में केन्द्रीय बजट पर 773 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोनस पड़ेगा।

76. सरकार, विशेष रूप से गैर-आयभिरता वाले और गैर-विकासात्मक क्षेत्रों में अत्यधिक सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखने जैसे महत्वपूर्ण विषय के प्रति जागरूक है। मैं सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे आगामी वर्ष देय होने वाले मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों संबंधी देयताओं को, किरायात करके तथा अनावश्यक व्यय को खत्म करके, अपनी बजट व्यवस्थाओं में समाविष्ट कर लें। इसलिये, मैं, अगले वर्ष के बजट में मंहगाई भत्ते के लिये एक मृण राशि के रूप में मात्र 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूँ। वह मुख्यतः सीमित बजट वाले उन छोटे विभागों हेतु उनकी सम्भावित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये है जो मंहगाई भत्तों की संवर्द्धित राशि को पूरी तरह समाविष्ट न कर पायें।

77. प्राप्ति पक्ष में, वर्ष 1989-90 की कराधान दर के अनुसार 57,988 करोड़ रुपए का सकल कर राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है तथा चालू वर्ष के 37,798 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में, राज्यों को करोड़ों में से उनका हिस्सा देने के पश्चात् निवल कर राजस्व 43,507 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

78. चालू वर्ष के 7,400 करोड़ रुपए के बाजार उधारों की तुलना में, मैंने 8,000 करोड़ रुपए के बाजार उधारों को हिसाब में लिया है। आगामी वर्ष में, वापसी अदायगी को घटाने के पश्चात् 4,327 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त होने की संभावना है जबकि चालू वर्ष में यह राशि 3,901 करोड़ रुपए थी। प्राप्तियों और व्यय के अन्य परिवर्तनों को देखते हुए, वर्ष 1989-90 की कराधान दरों के अनुसार आगामी वर्ष में 9,165 करोड़ रुपए का समग्र घाटा होने का अनुमान है।

79. अब तक आपने जिस धैर्यता के साथ मुझे सुना है, उसके बाद मैं उन करों और राहतों के अन्य विषयों के बारे में कहना चाहूंगा, जिसके लिए आप इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रत्यक्ष करों के संबंध में अपने प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा। मैं वैयक्तिक आयकर की दर संरचना में कुछ प्रमुख परिवर्तन शुरू कर रहा हूँ जिससे कि निम्न और मध्यम आय वाले समूहों की राहत मिल सके और

विभिन्न आय वर्गों में करदाताओं के लिए और अधिक गमतापूर्ण बचन में जुड़े हुए प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। मेरा प्रथम प्रस्ताव राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करने के वास्ते छूट की सीमा बढ़ाने का है। मैं वैयक्तिक आयकर की छूट-सीमा को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 22,000 रुपए कर रहा हूँ। मौटे तौर पर इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप लगभग 10 लाख व्यक्ति इस कर में मुक्त हो जाएंगे। नई छूट-सीमा निर्धारित करने में मुझे दो परस्पर विरोधी बातों को ध्यान में रखना पड़ा है। एक ओर, यह सच है कि निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति कीमतों में वृद्धि से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं और छूट-सीमा बढ़ाने का पर्याप्त औचित्य है। दूसरी ओर, सीमा बढ़ाने से कर-आधार संकीर्ण होता है और राजस्व की पर्याप्त हानि होती है, क्योंकि वृद्धि का लाभ सभी करदाताओं को होगा और यह केवल निचले आय स्तरों तक ही सीमित नहीं रहेगा। विशेषज्ञों की प्रायः यह राय रही है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए छूट की सीमा बढ़ाना न्यायोचित नहीं है। तथापि, जैसा कि मैं स्वभावतः कठोर स्थितियों में वचना चाहता हूँ, मैंने मध्यम मार्ग अपनाया है जो मेरे मतानुसार उपयुक्त और न्यायोचित है।

80. निम्न और मध्य आय वर्गों के व्यक्तियों को राहत के एक और उपाय के रूप में, मैं 20 प्रतिशत की निचली दर की, जो इस समय 25,000 रुपए तक उपलब्ध है, बढ़ाकर 30,000 रुपए कर रहा हूँ।

81. पिछले वर्ष रोजगार कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए 8 प्रतिशत की दर से एक अधिभार प्रारंभ किया गया था। इस रोजगार अधिभार को वापस लेने से रोजगार-प्रधान आयोजना के प्रति मेरी सतत प्रतिबद्धता के संबंध में मन्देह पैदा हो जाएगा। इसलिए, मेरे पास इस अधिभार को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब यह 75,000 रुपए की कर-योग्य आय से अधिक राशि पर लगेगा, जबकि इसकी वर्तमान सीमा 50,000 रुपए है।

82. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहन की विद्यमान स्कीमें आय से कटौतियों पर आधारित हैं। एक व्यक्ति को उस पर लागू कर की सर्वोच्च सीमान्त दर पर कर-राहत प्राप्त होती है। तदनुसार, इससे निम्न आय वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक आय वाले व्यक्ति को अधिक कर-भास प्राप्त होता है। इस असमानता को दूर करने की दृष्टि से मेरा प्रस्ताव द्वारा 80% के अन्तर्गत वचतों की सकल राशि पर कर-छूट की एक प्रणाली लागू करने का है। नई प्रणाली के अन्तर्गत, भविष्य-निधि, जीवन बीमा, राष्ट्रीय बचत पत्रों इत्यादि में अंशदान करने वाला व्यक्ति, पहले की भांति, ऐसी वचतों पर 20 प्रतिशत की दर के हिसाब से कर-छूट का हकदार होगा। दी जा सकने वाली अधिकतम कर-छूट की राशि सामान्यता 10,000 रुपए और

लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतकारों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और एथलीटों के मामलों में 14,000 रुपए होगी। मौटे तौर पर यह अब उपलब्ध अधिकतम राहत के बराबर है। सभी व्यक्तियों को बचतों की एक निश्चित राशि पर एक ही प्रकार का कर-लाभ प्राप्त होगा, चाहे उनकी आय का स्तर कुछ भी हो। निचले आय-कर दाता को लाभ प्राप्त होगा।

83. अब मैं अपने उपरोक्त प्रस्तावों के प्रभाव के बारे में बताता हूँ। एक व्यक्ति जिसकी मासिक वेतन आय 3,500 रुपए अर्थात् 42,000 रुपए प्रतिवर्ष है, जो भविष्य निर्धि और बीमा में 8,000 रुपए प्रति वर्ष बचाता है, इस समय 1,000 रुपए प्रतिवर्ष कर के रूप में अदा करता है। नई व्यवस्था के अन्तर्गत उसे कोई कर अदा नहीं करना पड़ेगा। उपरी आय वर्ग के लोगों को 10,000 रुपए की पूर्ण राहत प्राप्त करने के लिए 50,000 रुपए की बचत करनी होगी। पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत उन्हें इतनी राहत केवल 39,500 रुपए बचाकर ही प्राप्त हो जाती थी। मैं यहाँ यह भी उल्लेख कर दूँ कि एक समान कर-छूट की नई प्रणाली से नियोक्ताओं द्वारा स्रोत पर कटौती करने में काफी सरलता हो जाएगी।

84. बचत को और प्रोत्साहन के रूप में मेरा प्रस्ताव धारा 80 गग क के अन्तर्गत बचत प्रोत्साहनों के लिए इस समय उपलब्ध 30,000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का है। चूँकि इस मद के अन्तर्गत बचतें 'घटाने' के सिद्धांत पर आधारित हैं और जब उनकी निकासी की जाती है तो उन्हें फिर से आय में जोड़ दिया जाता है, कर-योग्य आय से कटौती की वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी।

85. इसके अतिरिक्त, 'इक्विटी संयोजित बचत स्कीम' (ई. एल. एस. एस.), जिसकी घोषणा पिछले वर्ष की गई थी, को अब 'घटाने' के सिद्धांत के आधार पर अन्तिम रूप दे दिया गया है। स्कीम के अन्तर्गत यूनिटों में किया गया निवेश कुल आय में से 10,000 रुपए की अधिकतम सीमा तक कटौती के लिए पात्र होगा। यूनिटों में निवेश पर वार्षिक प्रतिफल धारा 80ठ के अन्तर्गत कर रियायत के लिए पात्र होगा। म्यूच्युल निधियों द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर, यूनिटों की लागत दर्शाने वाली पूंजीगत राशि पर पुनः खरीद वाले वर्ष में आय के रूप में कर लगेगा और अधिशेष पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगेगा। अंततः इक्विटी संयोजित बचत स्कीम, धारा 80 गग के अन्तर्गत वर्तमान कटौती का स्थान लेगी। इसी बीच इस व्यवस्था को 31 मार्च, 1991 तक किए गए निवेशों के लिए भी लागू किया जा रहा है।

86. कुछ सीमा तक, शारीरिक रूप से विकलांग अथवा मानसिक रूप से अवरुद्ध ऐसे व्यक्तियों के माता-पिता तथा अभिभावकों की कठिनाई को दूर करने के प्रयास के रूप में,

जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपए तक है, मेरा प्रस्ताव ऐसे व्यक्तियों के चिकित्सीय उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए माता-पिता अथवा अभिभावक की कुल आय में से 6,000 रुपए तक की कटौती प्रदान करने का है।

87. मेरा प्रस्ताव, लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतकारों, अभिनेताओं और खिलाड़ियों, जिनमें एथलीट भी शामिल हैं, को उपलब्ध विदेशी मुद्राओं में व्यावसायिक आय के संबंध में कटौती को विद्यमान 25 प्रतिशत की दर से आय का 50 प्रतिशत तक अथवा भारत में लाई गई विदेशी मुद्रा का 75 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, बढ़ाने का है। प्रोफेसरों, अध्यापकों और अनुसंधानकर्ताओं के मामले में भी विद्यमान व्यवस्था को उदार बना दिया गया है, जिससे कि भारत में लाई गई विदेशी मुद्रा के 75 प्रतिशत की कटौती की छूट दी जा सके।

88. अब मैं कंपनी कर के संबंध में अपने प्रस्ताव रखूँगा। निगमित क्षेत्र ने प्रायः यह सवाल उठाया है कि कंपनी कर की दर अधिक है और इससे विकास और साथ ही कर अनुपालन में बाधा पहुंचती है। बारीकी से जांच करने पर मैंने देखा है कि दर दिखावटी रूप से अधिक है, क्योंकि इस प्रणाली में बहुत अधिक छूटों की व्यवस्था है। सभी अनुमत्य छूटों और कटौतियों के बाद प्रभावी दर काफी कम हो जाती है। बहुत सी बड़ी और ऊँचा लाभ कमाने वाली कंपनियां कर से बच जाती हैं और काफी समय से शुन्य कर अदा कर रही हैं। यही कारण है कि कर-राजस्व में कम्पनी क्षेत्र का अंशदान उनके द्वारा अर्जित किए गए लाभों के अनुरूप नहीं है और न ही वह राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप है। वर्तमान कर प्रणाली पूजी गहन उत्पादन के पक्ष में भी झुकी हुई है।

89. और अच्छा कर अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक दोहरी नीति अपनाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं निवेश भत्ते और निवेश जमा खाते जैसे प्रमुख प्रोत्साहनों को समाप्त कर रहा हूँ जिससे कि कंपनी क्षेत्र कर अदा करने से न बचत पाए, और ऐसा हो जाने पर मेरा प्रस्ताव व्यापक जन-धारित देशीय कंपनियों के लिए 40 प्रतिशत की कर दर निर्धारित करने और अन्य देशीय कंपनियों के लिए दरों में तदनुसूची परिवर्तन करने का है। इस दोहरी नीति से प्रभावी कर दर बढ़ जाएगी और 800 करोड़ रुपए का पर्याप्त अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा।

90. अब जिन प्रमुख कटौतियों की अनुमति होगी वे विदेशी मुद्रा अर्जित करने और नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने से संबंधित हैं। नए उद्योग स्थापित करने के लिए कटौती को कंपनियों के मामले में 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत और अन्यो के मामले में 20 प्रतिशत से बढ़ाकर

25 प्रतिशत किया जा रहा है। यह लाभ जिस अवधि में प्राप्त किया जा सकता है, उसे 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया जा रहा है।

91. प्रमुख छूटों को समाप्त कर देने से, आयकर अधिनियम की धारा 115वाँ में निर्दिष्ट न्यूनतम लाभों पर कर से संबंधित विशेष व्यवस्था को समाप्त करने का प्रश्न उठता है। तदनुसार मेरा प्रस्ताव 1991-92 निर्धारण वर्ष से उस व्यवस्था को समाप्त करने का है।

92. अन्तर-कंपनी लाभांशों के कर में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू कर रहा हूँ। इस समय किसी देशीय कंपनी द्वारा अन्य कंपनी से प्राप्त लाभांश आय का 60 प्रतिशत भाग कर से मुक्त है। कंपनियों के रूप में जो वस्तुतः अल्प जन-धारित होती हैं वैयक्तिक धन धारित करने की एक प्रवृत्ति है। वास्तविक निवेश, कार्यक्षमताओं को प्रोत्साहित करने और साथ ही वैयक्तिक धन धारित करने के लिए कंपनियों के उपयोग को हतोत्साहित करने की दृष्टि से मेरा प्रस्ताव, देशीय कंपनियों द्वारा अन्य देशीय कंपनियों से प्राप्त लाभांशों को उस पूरी सीमा तक मुक्त करने का है, जिसे वे स्वयं उस संबद्ध अवधि के दौरान लाभांश के रूप में घोषित करें। तथापि, अनुसूचित बैंक और लोग वित्तीय संस्थान, संक्षेप में, धारा 80 ड की व्यवस्थाओं द्वारा शासित होते रहेंगे, जैसा कि इस समय है।

93. मैंने कंपनी कर प्रणाली में जिसे सुधार का प्रस्ताव किया है उसका परिणाम सरलता में वृद्धि, कर-संरचना को सरल बनाना और इन छोटी तथा बड़ी कंपनियों के बीच निष्प्रभावी बनाना होगा। इसके साथ ही, इससे निर्यात और नए औद्योगिक उपक्रमों में निवेश के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा।

94. बहुत सारे लघु उद्योग सज्जेदारी में चलाए जाते हैं। मैं उनके लिए छूट की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने और करों की दरें उपयुक्त रूप से कम करने का प्रस्ताव करता हूँ।

95. पारिस्थितिक रूप से अव्यवस्थित क्षेत्रों के पुनरुद्धार से रोजगार के सृजन का उद्देश्य प्राप्त होता है, ईंधन की लकड़ी और चारे की पूर्ति बढ़ती है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणात्मक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। वनारोपण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मेरा प्रस्ताव धारा 35 ग ग ख और धारा 80 छ छ छ क की व्यवस्थाओं को उन करदाताओं पर लागू करने का है जो निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वनारोपण के कार्यक्रम अथवा कोष में अंशदान करें।

96. वैयक्तिक आयकर के मामले की तरह, मेरा प्रस्ताव 75,000 रुपये से अधिक की समस्त आय पर लगने वाले विद्यमान 8 प्रतिशत अधिभार को कंपनी करदाताओं पर भी जारी रखने का है।

97. मेरा प्रस्ताव उपहारों पर कर में भी एक प्रमुख परिवर्तन करने का है। आजकल उपहारों पर दाता के हाथ में कर लगता है, परन्तु दान प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त राशि को दिखाए जाने की कोई सीमा नहीं है। इसकी वजह से उपहारों की प्रणाली का प्रयोग, पूंजी को विभाजित करने और काले धन से बचने के लिए किया जाता है। हाल ही में कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने में आए हैं जबकि विवाहोत्सवों व अन्य समारोहों पर किए गए व्यय और आडम्बरपूर्ण खर्च को उपहारों में से वित्तपोषित किया गया बताया गया था। ऐसी प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से मैंने दाताओं पर वर्तमान उपहार-कर के स्थान पर दान-प्राप्तकर्ता आधारित उपहार-कर लगाने का निर्णय किया है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्तियों अथवा अपने खर्च को उपहारों में से वित्तपोषित बताएगा, उसे अब एक क्रमिक स्तर पर उपहार-कर देना होगा। इस प्रकार उसे इस उपहार का एक भाग राजस्व को उपहार के रूप में अन्तरित करने का सुख प्राप्त होगा।

98. दान प्राप्तकर्ता आधारित उपहार-कर का प्रमुख उद्देश्य राजस्व जुटाना नहीं है, बल्कि कर-अपवंचन और आडम्बरपूर्ण उपभोग को रोकना है। वैध उपहारों के मामले में सावधानी बरतने के उद्देश्य से 20,000 रुपये प्रतिवर्ष की बनियादी छूट सीमा रहेगी। 20,000 रुपये से अधिक परन्तु 50,000 रुपये से अनधिक के कुल उपहारों के मामले में उपहार-कर 20 प्रतिशत लगेगा; 50,000 रुपये से अधिक परन्तु 2 लाख रुपये से अनधिक के कुल उपहारों के मामले में 30 प्रतिशत, और 2 लाख रुपये से अधिक कुल उपहारों के मामले में 40 प्रतिशत उपहार-कर लगेगा। इसके अतिरिक्त मेरा प्रस्ताव विवाह के अवसर पर किसी एक व्यक्ति द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त उपहारों के संबंध में एक लाख रुपये की पर्याप्त अधिक सीमा निर्धारित करने का है। इसके अतिरिक्त सरकारी माध्यमों के जरिए विदेशी मुद्रा में प्राप्त उपहार भी छूट के पात्र होंगे।

99. मेरा प्रस्ताव, नई प्रणाली को 20 मार्च, 1990 को अथवा उसके पश्चात् दिए गए उपहारों पर लागू करने का है। परिणामतः इस तारीख को अथवा उसके बाद दिए गए उपहारों के संबंध में, दाताओं के हाथ में उपहारों पर कर लगाने संबंधी विद्यमान उपहार-कर अधिनियम का प्रवर्तन समाप्त हो जाएगा।

100. इस नई स्कीम को प्रभावी रूप देने के संबंध में विधान संसद् के चालू अधिवेशन के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।

101. प्रत्यक्ष कर कानूनों में अन्य छोटे परिवर्तनों के संबंध में, सदन का समय नहीं लेना चाहता हूँ।

102. जैसा कि मैंने पहले बताया है, कंपनी कर से राजस्व में 800 करोड़ रुपए तक का लाभ होगा। अच्छे अनुपालन को ध्यान में रखते हुए कंपनी कर के अतिरिक्त, आयकर से राजस्व में 250 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है। इस प्रकार प्रत्यक्ष करों के संबंध में 550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होगी।

103. अब मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा। मेरे प्रस्तावों में मुख्य रूप से सरलीकरण और इन्हें युक्तिसंगत बनाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही मैंने इस प्रकार से कुछ संसाधन जुटाने का भी प्रयास किया है कि उसका आम आदमी पर प्रभाव न पड़े और इसके साथ ही इससे तड़क-भड़क वाले उपभोग पर नियंत्रण हो सके। विकास और निर्यात के लिए प्रोत्साहनों को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया है। हमारे उद्योग में गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से शुल्क प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का भी प्रस्ताव है। मैंने पात क्षेत्रों, विशेष रूप से लघु उद्योग, कृषि और पर्यावरणात्मक सुरक्षा को राहत देने का भी प्रयत्न किया है। इन सभी उपायों के संबंध में वित्त विधेयक के व्याख्यात्मक जापन में कुछ विस्तार से चर्चा की गई है। गई है। मैं इन प्रस्तावों में से कुछेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

104. फिलहाल आयात शुल्क की दरें काफी फैली हुई हैं। दरों को युक्तिसंगत बनाने और उनकी विविधता को कम करने की दृष्टि से सीमाशुल्क की बुनियादी और सहायक शुल्क दरों को, अधिकांश मदों के संबंध में शुन्य से लेकर 125 प्रतिशत तक एक सीमित संख्या में खांचों में रखा जा रहा है। इसके अलावा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत और सरल बनाने के एक उपाय के रूप में बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं के संबंध में शुल्क दरों को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है। यद्यपि, युक्तिकरण के परिणामस्वरूप कतिपय वस्तुओं पर शुल्क दरें मामूली रूप से घट या बढ़ सकती हैं, किन्तु कुल मिलकर प्रस्तावों का उद्देश्य आमतौर पर राजस्व को तटस्थ रखना है। शुल्क के प्रत्येक परिच्छद में दरों की संख्या में कटौती करने से कर-निर्धारण सरल हो जाएगा। हमारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा कि मूलानुसार दरों में स्थिरता आए।

105. प्रथमतः मैं सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क में रियायतों जैसे अपने प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा।

106. हमारी विकास की प्रणाली में कृषि एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली अधिकांश निविष्टियों पर कर की दरें पहले से ही काफी कम रखी गई हैं। विनिर्दिष्ट कीटनाशी और कीटनाशी मध्यवर्तियों पर क्रमशः 70 प्रतिशत और 60 प्रतिशत की रियायती आयात शुल्क दरें लागू हैं। मैं कुछ और विनिर्दिष्ट थोक कीटनाशियों और कीटनाशी मध्यवर्तियों पर आयात शुल्क को इन स्तरों तक कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन प्रस्तावों से राजस्व में लगभग 16 करोड़ रुपए की हानि होगी।

107. तोरिया के तेल और सरसों के तेल के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, जिसका देश में प्रचुर उत्पादन होता है, मेरा प्रस्ताव रिफाईन्ड तोरिया तेल और सरसों तेल को पूर्णतः छूट देने का है, जिन पर आजकल 750 रुपए प्रति मी. टन का उत्पाद शुल्क लगता है। इस प्रस्ताव के कारण राजस्व में 8 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है।

108. मेरा प्रस्ताव अचारों पर से उत्पाद शुल्क विल्कुल हटाने का है और मेझे उम्मीद है कि इससे वजट में कुछ आस्वाद और कटपटापन आएगा।

109. इस समय काफी पर 78 रुपए से लेकर 105 रुपए प्रति क्विंटल की दर में उत्पाद शुल्क लगता है जो उसकी किस्म पर निर्भर करता है। कॉफी उत्पादकों को राहत के एक उपाय के रूप में रेरेमेरा प्रस्ताव शुल्क को घटाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल के एकसमान स्तर का करने का है। इस रियायत से 4 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

110. समुद्रीय उत्पन्न, देश के निर्यात में एक प्रमुख महत्वपूर्ण मद है। झींगा मछली के आयातित खाद्य को और किरायती बनाने की दृष्टि से मेरा प्रस्ताव इस मद पर शुल्क को घटाकर 25 प्रतिशत करने का है। खाद्य प्रसंस्करण और समुद्रीय खाद्य उद्योगों के आधुनिकीकरण में मदद करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव, इस समय कतिपय विनिर्दिष्ट मशीनरी के लिए उपलब्ध 40 प्रतिशत की रियायती आयात शुल्क दर को कुछ और मदों पर लागू करने का है।

111. पशु खाद्य की लागत कम करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव इसके उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले शीरे को पूर्ण उत्पाद शुल्क से विल्कुल मुक्त करने का है। मेरा प्रस्ताव पशुपालन और डेयरी प्रयोजनों के लिए अपेक्षित उपकरणों की कुछ मदों के संबंध में 40 प्रतिशत का रियायती आयात-शुल्क निर्धारित करने का भी है।

112. मेरा प्रस्ताव कुछ विशिष्टताओं वाले फुट-लवों को उत्पाद शुल्क से विल्कुल मुक्त करने का है ताकि कृषि-पम्पों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके।

113. इस समय हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में वन संपदा को संरक्षित रखने के एक उपाय के रूप में सेव की डिब्बाबंदी करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला क्राफ्ट कागज और क्राफ्ट कागज बोर्ड उत्पाद शुल्क से मुक्त है। मेरा प्रस्ताव इस रियायत को देश भर की सभी वागवानी उपज की डिब्बाबंदी पर लागू करने का है। इससे राजस्व में 5 करोड़ रुपए का नुकसान होने की उम्मीद है।

114. मेरा प्रस्ताव खादी और ग्रामोद्योग आयोग की इकाइयों द्वारा विनिर्मित, हाथ से बने कागज और कागज बोर्ड को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त करने का है चाहे शीट निर्माण की प्रक्रिया में बिजली का प्रयोग किया

गया हो। मेरा प्रस्ताव खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन इकाइयों द्वारा और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सहायता से चलाई जाने वाली इकाइयों द्वारा बनाए जाने वाले जूतों के संबंध में जूतों पर सीमा-शुल्क की छूट के प्रयोजनार्थ मूल्य सीमा को 75 रुपये से बढ़ा कर 100 रुपये प्रति जोड़ा करने का भी है।

115. लघु क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए मेरे भाषण के पिछले भाग में बताया गए उपायों के अलावा मेरा प्रस्ताव इस क्षेत्र को कुछ और राजकोषीय रियायतें देने का भी है। फिलहाल, लघु इकाइयों को 15 लाख रुपये मूल्य तक की वस्तुओं की निकासी के संबंध में उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त है, यदि ऐसी वस्तुएं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के केवल एक अध्याय के अन्तर्गत आती हों। मेरा प्रस्ताव 34 मूल्य सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का है। यदि ऐसी वस्तुएं उत्पाद शुल्क के एक से अधिक अध्याय के अन्तर्गत आती हों तो उनके संबंध में 30 लाख रुपये की मूल्य सीमा तक की वस्तुओं की निकासी के लिए उपलब्ध पूर्ण छूट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लघु क्षेत्र की इकाइयों के लिए छूट सीमा में वृद्धि करने से 67 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी। लघु क्षेत्र में विनिर्मित निविष्टियों के मामले में 5 प्रतिशत की सांकेतिक उधार की स्कीम की 1 अप्रैल, 1990 से एक और वर्ष के लिए जारी रखा जा रहा है। इसके अलावा केन्द्रीय उत्पाद लाइसेंस प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं की निकासी के मूल्य की सीमा विद्यमान 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की जा रही है। यह भी निर्णय किया गया है कि एक वर्ष में 20 लाख रुपये तक के मूल्य की निकासियों वाली लाइसेंस-शुदा लघु इकाइयों को उत्पादन, निकासी और शुल्क अदायगी के संबंध में केवल द्र्भासिक विवरण प्रस्तुत करना होगा। इन परिवर्तनों को 1 अप्रैल, 1990 से प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है।

116. जीवनरक्षक औषधियों की कीमतों को कम करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव रिफार्मिस्ड, जो एक तपेदिक-विरोधी औषध है, वाले कतिपय परिष्कृत नुस्कों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने का है। कतिपय जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट थोक औषधियों को भी सीमा शुल्क से मुक्त किया जा रहा है। मेरा प्रस्ताव कुछ विनिर्दिष्ट औषध मध्यवर्तियों पर आयात शुल्क को कम करके 90 प्रतिशत करने का है। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप लगभग 17 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

117. हाल ही में हुई, कुछ दुखद घटनाओं की हम सभी को जानकारी है, जिनमें अस्वास्थ्यकर रूप से पैक किए हुए अम्ल-शिरा द्रव्यों का उपयोग किया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि औषध निर्माण उद्योग

की अपूर्ति-दूषित पैकेजिंग की नवीनतम तकनीकों के अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, मेरा प्रस्ताव इस उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अपूर्ति-दूषित फार्म फिल सील मशीनों पर आयात शुल्क को 147.25 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घटाकर 40 प्रतिशत करने का है।

118. कुछ जीवनरक्षक उपस्करों पर आयात शुल्क में पूर्ण छूट प्राप्त है। मेरा प्रस्ताव, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ विनिर्दिष्ट यंत्रों और निरोपणों पर भी इस छूट को लागू करने का है। मैं श्रव्य साधनों के कल-पूजों पर भी सीमा शुल्क में कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूं।

119. मेरा प्रस्ताव होम्योपैथिक औषधियों और ऐसी औषधियों के निर्माण को कतिपय निविष्टियों पर सीमा शुल्क को कम करने का है। इसमें राजस्व में लगभग 5 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

120. औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने और निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी को कुछ रियायतें देने का है।

121. एक ऐसी भावना है कि हमारे निर्यात, पूंजीगत उपस्कर के आयात की अधिक लागत के कारण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता करने में सक्षम नहीं है। पूंजीगत विनिर्माता-निर्यातकों को उपयुक्त निर्यात दायित्व के विरुद्ध रियायती शुल्क दर पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार की जा रही है। मोटे तौर पर, स्कीम के अन्तर्गत आयातित एक विनिर्दिष्ट मूल्य सीमा तक पूंजीगत वस्तुएं 25 प्रतिशत के रियायती आयात शुल्क की हकदार होंगी। यह इस शर्त पर होगा कि आयात की गई पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य की कम से कम तीन गुना वस्तुएं, आयात किए जाने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के अन्दर निर्यात की जाएं। इस स्कीम के ब्यौरों की घोषणा, नई आयात और निर्यात नीति में की जाएगी।

122. विभिन्न निर्यात-प्रधान क्षेत्रों के लिए आवश्यक मशीनरी पर समय-समय पर रियायती आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। मैं इस रियायत को खड़े ब्रैलिंग उद्योग और फोर्ज्ड हेड दस्त उद्योग के लिए मशीनरी की विनिर्दिष्ट मदों पर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। इस रियायत के फलस्वरूप राजस्व में 8 करोड़ रुपये की हानि होगी।

123. निवेश को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी पूंजीगत क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव ऐसी मशीनरी पर चयनात्मक आधार पर 5 प्रतिशतों तक विन्मुक्तों तक उत्पाद शुल्क को कम करने का है। इस

रियायत के फलस्वरूप राजस्व में 60 करोड़ रुपए तक की हानि होगी। मैं उन व्यक्तियों में से एक हूँ जो यह विश्वास करते हैं कि स्वदेशी पूँजीगत वस्तु क्षेत्र आत्म-निर्भरता की दिशा में बढ़ने के लिए एक अनिवार्य अंग है। मुझे उम्मीद है कि उत्पाद शुल्क में कटौती करने से हमारा पूँजीगत उपस्कर और अधिक प्रतियोगी तथा आधुनिकीकरण की दिशा में अग्रसर होगा।

124. औद्योगिक इकाइयों को गुणवत्ता के उन्नयन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव विनिर्दिष्ट यंत्रों और उपस्करों पर 40 प्रतिशत का रियायती आयात शुल्क निर्धारित करने का है। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप राजस्व में लगभग 30 करोड़ रुपए की हानि होगी। स्वदेशी उत्पादों की कीमत में सुधार करने के हित में राजस्व की यह पर्याप्त हानि उपयोगी है।

125. और अच्छे पर्यावरण-आत्मक संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के हक में मेरा प्रस्ताव 40 प्रतिशत के वर्तमान रियायती आयात शुल्क को कुछ और विनिर्दिष्ट वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों पर लागू करने का है। इसके साथ ही मेरा प्रस्ताव कतिपय विनिर्दिष्ट प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों पर उत्पाद शुल्क को 15 प्रतिशत में कम करके 5 प्रतिशत करने का है।

126. हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं के उन्नयन के लिए भारी मात्रा में निवेश किए जाने की आवश्यकता है। राहत के एक उपाय के रूप में मेरा प्रस्ताव, भारत के राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण द्वारा आयात किए जाने वाले नौचालन, संचार, वायु यातायात नियंत्रण और अवतरण उपस्करों पर आयात शुल्क को कम करके 25 प्रतिशत के स्तर तक करने का है। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप 7.5 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

127. ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, मैं दूरसंचार के विनिर्दिष्ट उपस्करों पर उत्पाद-शुल्क की वर्तमान 20 प्रतिशत की दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे राजस्व में 15 करोड़ रुपए की हानि होगी।

128. मैं शुल्क बैंल बैटरियों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 35 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस राहत से राजस्व में 10 करोड़ रुपए की हानि होगी।

129. यह अभ्यावेदन किया जाता रहा है कि वीडियो के माध्यम से की जाने वाली वस्तुता के कारण फिल्म उद्योग की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से सिनेमाघरों में फिल्म के प्रिंटों को एक साथ चालू करके इस संकट का सामना करने में सहायता देने के उद्देश्य से, मैं फीचर फिल्मों को उत्पाद शुल्क से पूरी

तरह से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप राजस्व में 8 करोड़ रुपए की हानि होगी। मुझे आशा है कि इस प्रोत्साहन से, फिल्म व्यापार, जिसमें संदी आ गई थी, फिर से तेजी पकड़ लेगा।

130. समाचारपत्र उद्योग को राहत देने के उद्देश्य से मैं मानक अखबारी कागज पर आयात शुल्क को कम करके 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

131. प्रशासनिक सरलीकरण की दृष्टि से, मैं ट्रकों के ढाँचों के निर्माण कार्य, जो अधिकांश रूप से असंगठित क्षेत्र में होता है, पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को वहाँ से अंतरित करके मोटर वाहन चेसिस पर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

132. अब मैं वस्त्र उद्योग संबंधी प्रस्तावों के पैकेज का उल्लेख करूँगा। इन प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य कर-ढाँचे को सरल और युक्ति-संगत बनाना, कर संबंधी चोरियों की संभावनाओं को न्यूनतम करना तथा सस्ते वस्त्रों की अधिकांश श्रेणियों पर शुल्क की कम दरें सुनिश्चित करना है। इस संबंध में अनिवार्य रूप से दो प्रकार के प्रस्ताव हैं। पहले प्रकार के प्रस्ताव वस्त्र-स्तर पर शुल्क को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित हैं तथा दूसरे प्रकार के प्रस्ताव मानव-निर्मित वस्त्रों और धागों तथा इसके साथ ही उनके निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले मध्यवर्तियों पर उत्पाद तथा आयात शुल्कों में परिवर्तनों से संबंधित हैं।

133. हथकरघा बुनकरों की दुर्दशा के बारे में अधिकाधिक चिन्ता व्यक्त की जा रही है। आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि उनकी कठिनाइयों के मुख्य कारणों में से एक कारण यह है कि प्रसंस्करण स्तर पर ही व्यापक रूप से कर अपवचनाओं की वजह से इस क्षेत्र को दी गई कर संबंधी राहतें निष्प्रभावी हो जाती हैं। इस प्रकार, इस विचार से लगभग सभी सहमत हैं कि उत्पाद शुल्क को वस्त्रों से हटाकर धागों पर लगा दिया जाये, जिसका मैं भी समर्थन करता हूँ। तथापि, मानव-निर्मित वस्त्रों के मामले में समस्त शुल्क बिक्री कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में हैं। अतः, शुल्क प्रणाली में कोई भी परिवर्तन राज्यों के साथ परामर्श करने के पश्चात् ही किया जा सकता है। इस संबंध में, मेरा शीघ्र ही मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श करने का प्रस्ताव है।

134. तथापि, सूती वस्त्रों पर शुल्क का एक भाग मूल उत्पाद शुल्क के रूप में होता है। प्रथम उपाय के तौर पर, मैं सूती वस्त्रों पर लगे समस्त मूल शुल्क को अंतरित करके धागों पर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। चूंकि हथकरघों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले लच्छेदार धागे शुल्क से मुक्त ही रहेंगे, इससे लच्छेदार धागों और

जंकु धागों के सूत्रों के बीच का अंतर बढ़ जायेगा तथा इससे हथकरघा वस्त्रों की प्रतिस्पर्धायुक्तता में पर्याप्त सुधार आयेगा।

135. चूंकि राज्यों में परामर्श किये बिना, प्रसंस्करण स्तर पर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को फिलहाल धागों पर नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए मैंने वस्त्रों पर शुल्क-प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया है। मानव-निर्मित वस्त्रों के मामले में कर खण्डों की संख्या को इस ढंग में कम किया जा रहा है कि वस्त्रों पर लगने वाले शुल्क अधिक समतुल्य हो जायें तथा कर संबंधी कानूनों को और बेहतर ढंग से लागू किया जाए। मुझे विश्वास है कि इस सुविधा से कर अपवंचना में भारी कमी आयेगी तथा इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं में सुधार होगा।

136. अब मैं मानव-निर्मित रेशों, धागों तथा उनके निर्माण के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले मध्यवर्तियों का उल्लेख करूंगा। माननीय सदस्यों की स्मरण होगा कि वर्ष 1985 तथा 1988 में मानव-निर्मित वस्त्रों पर शुल्कों में पर्याप्त रूप से कमी की गई थी। यद्यपि, करों के भार को कम किया गया था, लेकिन इस प्रकार की शिकायतें मिलती रही हैं कि उपभोक्ता की तद्नुसार लाभ प्राप्त नहीं हुए। इसलिए, मैंने विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अतिरिक्त बोझ को सहन किये जाने वाली क्षमता को ध्यान में रखते हुए शुल्क-संरचना में संशोधन करने का प्रयास किया है। इससे हथकरघा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धायुक्तता में सहायता मिलेगी जिसमें मुख्य रूप से सूती होते हैं। मैं जिन मुख्य परिवर्तनों का प्रस्ताव कर रहा हूं, वे निम्नलिखित हैं:

—पी.टी.ए. पर 4.40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा डी.एम.टी. पर 3.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मूल उत्पाद शुल्क लगाना, जिससे 80 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

—पोलिएस्टर फिलामेंट धागों पर मूल उत्पाद शुल्क को लगभग 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति किलोग्राम तथा नायलोन फिलामेंट धागों पर लगभग 37 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम करके मूल उत्पाद शुल्क में वृद्धि करना जिससे 156 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

—विस्कोज स्टेपल फाइबर पर मूल उत्पाद शुल्क को 7 रुपए से बढ़ाकर 8.50 रुपए प्रति किलोग्राम करना जिससे 15 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

—पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर पर मूल शुल्क को 14 रुपए से बढ़ाकर 8.50 रुपए प्रति किलोग्राम करना जिससे 65 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी, तथा

—विभिन्न पोलिएस्टर ब्लेंडिड धागों पर मूल शुल्कों में कुछ कमी करना।

137. इस उद्योग में कुछ मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैं आयात शुल्कों को कम करने का प्रस्ताव करता हूं जो निम्नलिखित हैं:

—डी.एम.टी. और पी.टी.ए. पर 195 प्रतिशत से 150 प्रतिशत,

—एन.एफ.वार्ट. पर 130 से 100 प्रतिशत,

—पी. एफ. वाई. पर 205 से 180 प्रतिशत, तथा

—बी. एस. एफ. पर 55 प्रतिशत से 40 प्रतिशत। शुल्कों में इन कटौतियों से राजस्व में मामूली सी हानि ही होगी क्योंकि वास्तविक आयातों की मात्रा अधिक नहीं होने की संभावना है।

138. एम.ई.जी. के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए, मैं इस मद पर आयात शुल्क को 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके परिणामस्वरूप लगभग 48 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

139. माननीय सदस्यों की स्मरण होगा कि समाज के कमजोर वर्गों को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने और हथकरघा क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये, वस्त्र और वस्त्र-उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1978 में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया था। शुल्क की वर्तमान दर सामान्यतः मूल उत्पाद शुल्क की 13.64 प्रतिशत है। इस शुल्क के अतिरिक्त खादी व अन्य हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ वस्त्रों पर 2.5 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से एक उप-कर लगाया जाता है। मैं इन दोनों शुल्कों को एक साथ मिला कर अतिरिक्त शुल्क की दर को मूल उत्पाद शुल्क के 13.64 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

140. इसके अतिरिक्त, वस्त्रों के बारे में कुछ अन्य युक्तिकरण उपाय भी हैं, जिनमें एथ्रीलिक फाइबर, पोली-प्रोपीलीन स्टेपल फाइबर तथा फिलामेंट यार्न आदि पर शुल्क-दरों में मामूली समायोजन भी सम्मिलित है जिसका राजस्व पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

141. पटसन उद्योग को अपने उत्पादों के विविधकरण के लिये प्रोत्साहन की आवश्यकता है। मेरा प्रस्ताव पटसन के कम्बलों, फर्श की दरियों, चटाईयों तथा विरजित, मुद्रित और रंगे हुये पटसन के वस्त्रों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से मुक्त करने का है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की इकाइयों को आपूर्ति किये जाने वाले पटसन के लिये उपलब्ध शुल्क संबंधी पूरी छूट हस्ताक्षिप्त क्षेत्र पर भी लागू की जा रही है।



142. मुझे आशा है कि अब तक पर्याप्त राहतों का अनुभव करने के पश्चात् माननीय सदस्य अब कुछ राजस्व उपार्जन उपायों के बारे में असंतोष प्रकट नहीं करेंगे।

143. मुझे विश्वास है कि धूम्रपान करने वाले मेरे मित्रगणों के परिवारों के सदस्य, उनके स्वास्थ्य के हितों की दृष्टि से, सिगरेट पर उत्पाद शुल्क की दरों में वृद्धि की अपेक्षा कर रहे होंगे। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। शुल्क में वृद्धि की दर दस सिगरेट वाले प्रति पैकेट पर, सस्ती सिगरेटों के लिये 15 पैसे तथा महंगी सिगरेटों के लिये 75 पैसे होगी। 60 मिलीमीटर तक की लम्बाई वाली बिना फिल्टर वाली सिगरेटों पर शुल्क दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं साथ ही यह भी बता दूँ कि बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन करने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस उपाय से 131 करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पाद राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। इससे भी अधिक प्रसन्नता मुझे तब होगी यदि सिगरेट की खपत में गिरावट होने से मेरी वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ और भी कम हो जाएँ।

144. सहानुभूति दर्शाते हुए, पान मसाला पर उत्पाद शुल्क की दरों में भी कुछ बढ़ोत्तरी की जा रही है जिससे 6 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

145. मैं कोको तथा उससे बनी वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क की दर 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत, जैम, मामालिउस आदि पर 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत तथा आईस-क्रीम, जिस पर अभी तक कोई शुल्क नहीं था, पर 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इन उपायों से 26 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

146. मदन इस बात से सहमत होगा कि समाज के धनी वर्गों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं पर करों का अधिक बोझ पड़ना चाहिये। मैं, माईक्रोवेव ओवन, वाशिंग मशीन, श्रव्य-प्रणालियों की कुछ महंगी किस्मों और बीड़ियों कैसेट रिकार्डर तथा प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिकी खेलों तथा अपेक्षा-कृत अधिक ऊँची कीमतों वाले खाना बनाने के साधनों (चूल्हों) जैसी कीमती वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ।

147. मैं, मोटर कारों पर उत्पाद शुल्क 35 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे 79 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। दो-पहियों और ट्रैक्टरों पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन करने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है।

148. रेफ्रिजरेटरों, 1.5 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले एयर-कंडीनरों तथा आटोमोर्टिव गैस कम्प्रेसरों पर कुछ विनिर्दिष्ट शुल्क दरों में वृद्धि की जा रही है। मैं कारों के एयर-कंडीशनिंग पुर्जों, जिनमें उनकी किट का सामान

भी शामिल है, पर उत्पादन शुल्क 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे 14 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

149. कुछ किस्मों को छोड़कर, टायर और ट्यूबों पर अभी विनिर्दिष्ट दरों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। मूल्यों में लगातार वृद्धि होने के कारण, इन मदों पर मूल्यों की तुलना में शुल्क भार कम रह गया है। उपचारात्मक उपाय के रूप में मैं टायर और ट्यूबों की वर्तमान विनिर्दिष्ट दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, ट्रैक्टर, ट्रैलर और दो-पहिया वाहनों के टायर और ट्यूबों पर शुल्क में वृद्धि करने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है। युक्तिकरण संबंधी अन्य उपायों के साथ-साथ इससे लगभग 40 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

150. मैं लोहे और इस्पात पर मूल शुल्कों की विनिर्दिष्ट दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। सामान्य रूप से, स्टेनलेस स्टील की मदों के मामले में 500 रुपए प्रति मीट्रिक टन तथा अन्य मदों के मामले में 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से वृद्धि होगी। शुल्क-योग्य अनुप्रवाहगामी उत्पादों के मामले में, 'मोडवाट' ब्रेडिट पहले की तरह उपलब्ध होता रहेगा। इस प्रस्ताव से 104 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

151. इस समय, अधिकांश स्टेनलेस इस्पात तथा उससे बनी वस्तुओं पर आयात शुल्क की कुल दर 345 प्रतिशत है। मैं इस दर को कम करके 200 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन मदों पर तथा इस्पात की अन्य मदों पर सीमा शुल्क संबंधी प्रस्तावों से 10 करोड़ रुपए तक की राजस्व हानि होने का अनुमान है।

152. इस समय, देश में एल्युमीनियम का फलतू उत्पादन हो रहा है। आयात को हतोत्साहित करने की दृष्टि से, मैं एल्युमीनियम की सिल्लियों पर मूल सीमा शुल्क को बढ़ा कर 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

153. प्लास्टिक के मुख्य कच्चे माल पर 30 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क लगता है। तथापि, पोलिस्टीरिन पर शुल्क की दर मात्र 20 प्रतिशत है। युक्तिकरण के उपाय के रूप में, मैं इस दर को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

154. मैं, चमड़े के कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पेस्ट ग्रेड पी.वी.सी. पर मूल उत्पाद शुल्क को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि कर अपवंचन को रोका

जा सके। पी.वी.सी. आवरण वाले वस्तुओं पर उत्पाद शुल्कों में भी वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है। इन उपायों से 17.5 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है।

155. इस समय, पेंट और वार्निशों की विभिन्न किस्मों की मर्दों पर 15 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक के बीच की अलग-अलग दरों पर उत्पाद शुल्क लगता है। मैं वर्तमान पांच दरों के स्थान पर, 15 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के केवल दो ही स्तर रखकर दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत, इंसुलेटिंग वार्निशों और जल-आधारित पेंटों पर 15 प्रतिशत की दर से तथा तेल पर आधारित और प्लास्टिक पर आधारित सजावट के पेंटों पर 30 प्रतिशत की दर एकसमान उत्पाद शुल्क निर्धारित किया जायेगा। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप 9 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी।

156. इस समय, देश में ही निर्मित वस्तुओं पर मूल उत्पाद शुल्क के 1/20 भाग की दर से विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। तथापि, आयातित वस्तुओं पर प्रति-संतुलनकारी सीमा शुल्क का परिकलन करने के लिये, विशेष उत्पाद शुल्क को हिसाब में नहीं लिया जाता है। मेरे विचार से इस भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि उत्पाद शुल्क, जिसमें विशेष उत्पाद शुल्क भी सम्मिलित हो, के आधार पर, आयातित वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिये। इस प्रस्ताव से 60 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

157. विदेश से आने वाले यात्रियों की आहुय मुक्त भत्ते से संबंधित माल-असबाब (सामान) नियमों में संशोधन किया जा रहा है। सामान्य मुक्त भत्ते को 1,250 रुपये प्रति यात्री के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति यात्री किया जा रहा है। इस सीमा से अधिक सामान के लिए 250 प्रतिशत की एकसमान दर लगेगी जबकि विद्यमान दर 175 प्रतिशत और 245 प्रतिशत है। मैं एक वर्ष से अधिक अवधि तक टहरने के पश्चात् विदेश से आने वाले यात्रियों द्वारा लाई गई विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर, कुछ शर्तों के अधीन, 25 प्रतिशत की एकसमान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव भी करता हूँ। संशोधित दर पहली अप्रैल, 1990 से प्रभावी होगी।

158. सहायक सीमा शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क की वर्तमान दरों को जारी रखने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

159. जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, पिछले वर्ष के बजट में अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर लागू किया गया था। यह कर कुल हवाई किराए अर्थात् मूल

किराए के एक घटक के 10 प्रतिशत पर लगता है। मैं पूरे हवाई यात्रा किराए पर वर्तमान दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से 15 करोड़ रुपए का अनुमानित राजस्व लाभ होगा।

160. जैसा कि मैंने अपने भाषण के पहले भाग में जिक्र किया है, हाल ही के वर्षों में हमारी पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में तेजी से वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यों को यह भी जानकारी है कि विदेशों में पेट्रोलियम के मूल्यों में कठोरता आ रही है। आयात पर अधिक निर्भरता के कारण काफी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है और जिसके फलस्वरूप कुल मिलाकर विदेशी उधारों में वृद्धि हो रही है। अब पेट्रोलियम उत्पादों के स्वदेशी मूल्यों की पुनरीक्षा करना आवश्यक हो गया है, ग्राम आदमी के हितों का ध्यान में रखते हुए, मिट्टी के तेल और एल.पी.जी. सिलिंडरों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी, मैं पुनः यह कहता हूँ कि इनके मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी। उर्वरक और अन्य उपयोगों के लिए नेफ्था, प्राकृतिक गैस, उद्योग के लिए भट्टी के तेल, मझों के लिए विटमैन और किसानों के लिए लो स्पीड डीजल तेल के मूल्यों में भी कोई वृद्धि नहीं होगी। जिन चुनी हुई मर्दों के मूल्यों में आज मध्य रात्रि में संशोधन किया जा रहे हैं वे हैं: सोलर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल तेल और स्वदेशी उपयोगकर्ताओं के लिए विमानों टरबार्न ईंधन यद्यपि मोटर स्प्रेट के मूल्य में 1.25 रुपए प्रति लिटर भंडार मूल्य की, तथापि हाई स्पीड डीजल तेल के मूल्य में 54 पैसे प्रति लिटर की वृद्धि होगी। विमानों टरबार्न ईंधन के मूल्य में 1.320.45 रुपए प्रति किलोलिटर की वृद्धि होगी। खुदरा मूल्यों में वृद्धि, परिवहन प्रभारों और स्थानीय करों तथा शुल्कों के प्रभाव के आधार पर, प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न होगी। मैं कीमतों में संशोधन के फलस्वरूप नेत्र कम्पनियों को होने वाले लाभ लेवी के एक हिस्से की स्मेटने का प्रस्ताव करता हूँ। कच्चे (क्रूड) तेल पर लगने वाले आयात शुल्क को 1.060 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1.500 रुपए प्रति मी. टन किया जा रहा है। इसमें 836 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

161. सरकार को कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करने के इस दुःखद कार्य को करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन गंभीर राजकोपीय स्थिति, बढ़ते हुए विदेशी ऋण और भुगतान संतुलन की कठिन स्थिति की वजह से हमारे पास यही कठोर विकल्प रह गए थे। हम अपनी आर्थिक आजादी और आत्मनिर्भरता को खतरे में डाल कर ही इन विकल्पों में वच सकते थे।

162. मैंने उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क टेरिफ में परिवर्तन करने के आशय से वित्त विधेयक में भी कठिन संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। ये संशोधन सामान्यतः समर्थनकारी उपबंध हैं और राजस्व उपार्जन की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। इनके अतिरिक्त कुछेक मौजूदा

अधिसूचनाओं में भी संशोधन करने के प्रस्ताव किए जा रहे हैं। इस सदन का मूल्यवान समय बचाने की दृष्टि से मैं उन सभी प्रस्तावों की दोहराना नहीं चाहता।

163. ऊपर बताए गए उत्पाद-शुल्कों में परिवर्तनों से संबंधित प्रस्तावों के परिणामस्वरूप उत्पाद-शुल्कों से 778.63 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। जिन रियायतों और राहतों की घोषणा की गई है उनकी राशि 388.44 करोड़ रुपए है। उत्पाद शुल्कों से प्राप्त होने वाले 390.19 करोड़ रुपए के निबल अतिरिक्त विभाज्य राजस्व में से केन्द्र के हिस्से में 217.12 करोड़ रुपए और राज्यों के हिस्से में 173.07 करोड़ रुपए की राशि आएगी।

164. मेरे द्वारा सीमा शुल्कों के क्षेत्र में किए गए कर प्रयासों से 979.79 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। 144.76 करोड़ रुपए की राहतों को घटाकर केन्द्र को 835.03 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर में परिवर्तनों से 15 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

165. सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों में परिवर्तनों को 20 मार्च, 1990 से प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएंगी।

166. अब मुझे अपने माननीय सहयोगी, संचार मंत्री, की ओर से कुछ कहना है। डाक सेवा में काफी अधिक संख्या में लोग कार्यरत हैं और वेतन तथा भत्ते, डाक विभाग के कार्यचालन व्ययों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त मंजूर करने और अन्य कार्य चालन खर्चों में वृद्धियां होने से इन लागतों में काफी अधिक वृद्धि होती है। डाक दरें अधिकांश सेवाओं की प्रत्यक्ष लागत को भी पूरा नहीं करती हैं। इसलिए कुछ डाक सेवाओं के लिए दरों में संशोधन अपरिहार्य हो गया है। तथापि, आम आदमी के हित में और सूचना के व्यापक प्रसार के लिए, साधारण पोस्ट कार्ड और रजिस्ट्रीकृत समाचार-पत्रों के लिए टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। छापे हुए पोस्टकार्ड, जोकि मुख्यतः व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं, की दर को 40 पैसे से बढ़ाकर 60 पैसे किया जा रहा है। अन्तर्देशीय। पत्र 50 पैसे जिसमें लेखन सामग्री प्रभार शामिल है, से 75 पैसे की समेकित राशि का किया जा रहा है और लिफाफों की दर को, बिना किसी लेखन सामग्री प्रभार के प्रति, 20 ग्राम के लिए एक रुपए की एक समान दर किया जा रहा है। कतिपय अन्य परिवर्तन भी किए जा रहे हैं जिनके संबंध में बजट दस्तावेजों के साथ परिचालित किए गए ज्ञापन में बताया गया है। डाक दरों में किए गए परिवर्तन, वित्त विधेयक के पारित होने के पश्चात, अधिसूचित की गई तारीख से प्रभावी होंगे। प्रस्तावित

संशोधनों से पूरे एक वर्ष में लगभग 207 करोड़ रुपए और 1990-91 में लगभग 172 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

167. माननीय सदस्यों को याद होगा कि 46वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1982 द्वारा माल के प्रेषण, जहां ऐसा प्रेषण अन्तर-राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान होता है, पर कर लगाने के लिए संसद की शक्तियां प्रदान की गई थीं। तथापि, इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया के संबंध में विचारों में भिन्नता रही है और इस विषय पर मुख्य मंत्रियों की अनेक बैठकों में चर्चा की गई है। इस संबंध में व्यापक प्रतिमानों को अब तय कर लिया गया है और केन्द्र तथा राज्य दोनों द्वारा इस कर से छूट देने के संबंध में मार्ग निर्देश तैयार करने के लिए मुख्य मंत्रियों की एक समिति नियुक्त की गई थी। इस विषय में अन्तिम दृष्टिकोण अपनाने के लिए शीघ्र ही मैं मुख्य मंत्रियों से परामर्श करने का प्रस्ताव करता हूं।

168. मैंने पहले जिक्र किया है कि करों की वर्तमान दरों पर बजट घाटा 9,165 करोड़ रुपए का होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों और संशोधित डाक टैरिफ में प्रस्तावित संशोधनों से निबल अतिरिक्त प्राप्ति को हिसाब में लेने के पश्चात अगले वर्ष के लिए 7,206 करोड़ रु. के घाटे का अनुमान लगाया गया है। माननीय सदस्य देखेंगे कि यह घाटा, संशोधित अनुमान 1989-90 में 11,750 करोड़ रुपए के घाटे की तुलना में काफी कम है। सही संकेत देने और मुद्रास्फोटिकारी दबावों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मैंने अगले वर्ष के घाटे को चालू वर्ष के 7,337 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में भी कम रखने का प्रयत्न किया है।

169. यह मेरा पक्का निश्चय है कि बजट में दिया गया घाटा और नहीं बढ़ना चाहिए। वजटीय स्थिति में होने वाली वास्तविक घटना चक्रों की छमाही पुनरीक्षा की जाएगी, और घाटे के संबंध में कार्य-निष्पादन के बारे में जनता और संसद को सूचना दी जाती रहेगी।

170. हमें राजकोषीय और कर प्रणाली को अधिक स्थायी और पूर्व-सूचनीय बनाने की आवश्यकता है। हर वर्ष कर दरों और कर कानूनों में भारी संख्या में परिवर्तन करने की प्रथा, अनिश्चितता पैदा करने के अलावा, प्रशासनिक तंत्र पर भारी बोझ डालती है। यह अनुपालन को भी प्रभावित करती है और मुकदमे बाजी में वृद्धि करती है। हालांकि कर दरों और कर कानूनों में कुछ परिवर्तन अपरिहार्य हैं फिर भी यह वांछनीय है कि नियादी ढांचे को कम से कम कुछ समय के लिए स्थिर रखा जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार दीर्घकालीन राजकोषीय नीति पर एक प्रपत्र संसद में प्रस्तुत करेगी।

171. इसके साथ ही, मैं अपनी मेहनत के अन्तिम छोर पर पहुँच गया हूँ। हम एक ऐसी राजकोषीय स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें आर्थिक गुरुद्वता और हमारे देश की स्थिरता को खतरा है। हमारे सामने यह विकल्प था कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलें, अधिक उधार लिया जाए और अधिक खपत की जाए, अथवा अब सुधारात्मक कार्रवाई की जाए, चाहे कितनी भी कठिन हो। हमने अपना विकल्प खोज लिया है। हमने अमीरों से कुछ साधन लिए हैं और उनका गरीब और आम आदमी को कुछ राहत देने के लिए प्रयोग किया है। हमने बजटीय घाटे को सीमित करने और मुद्रास्फीतिकारी दवावों को नियंत्रित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने आयोजना और निवेश के सन्तुजन को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर तथा रोजगार के पक्ष में झुकाया है।

172. विज्ञान में रुचि रखने वाले एक व्यक्ति के रूप में और व्यावहारिक समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध होने के नाते मैं प्रयोगों और इसके परिणाम को कसौटी समझता हूँ जिनके आधार पर सभी सामाजिक और आर्थिक जान और नीतियों की प्रासंगिकता का परीक्षण किया जा सकता है।

173. यह गांधी जी, जय प्रकाश, आचार्य नरेन्द्र देव जैसे समाजार्थिक प्रयोगकर्ताओं की अनथक खोज के प्रयोगवाद और सारांश का निचोड़ है।

174. माननीय अध्यक्ष, अपने ऐसे प्रयोगवादी दृष्टिकोण के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ मैं यह बजट इस महान सदन को समानता और आत्म-निर्भरता के साथ विकास का एक दीर्घविक्रम उद्देश्य सुनिश्चित करने की दिशा में सतत और दृढ़ अल्पकालिक साधन के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। अपने इस प्रयास में मैं लोगों का उनके द्वारा प्रजातांत्रिक ढंग से चुने गए इस सम्माननीय संसद के माध्यम से पूर्ण समर्थन की कामना करता हूँ।

175. महोदय, मैं इस बजट को स्वीकृति के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

श्रीमती जानकी कथपालिया, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

### BUDGET DIVISION

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 1990

M/Finance (DEA) U. O. No. 591/JS (Bud.) 90.—  
The following is published for general information of the Public :—

Budget 1990-91

Speech of

Shri PROF. Madhu Dandavate

Minister of Finance

19th March, 1990

PART A

Mr. Speaker,

I deem it a great privilege to have the opportunity to present the first Budget of the new Government.

2. Over a hundred days ago winds of political change swept the country. The new Government, which secured a massive vote of confidence of this Honourable House transcending political affiliations, made a tryst with the nation to respect and implement the mandate it received from the people.

3. Let me, at the outset, deal with the economic situation that we inherited from the previous Government. I do so not in a spirit of acrimony but with a view to revealing to the House the ground realities. The Central Government's budgetary deficit was Rs. 13,790 crores as on 1st December, 1989, a level nearly double the deficit projected for the whole year in the 1989-90 budget. Wholesale prices had risen by 6.6 per cent since the beginning of the financial year. The balance of payment was under strain and foreign exchange reserves (excluding gold and SDRs) were down to around Rs. 5000 crores. Stocks of foodgrains had fallen to 11 million tonnes.

4. On a broader scale, the Economic Survey which was placed on the Table of the House only a few days ago deals with the current economic situation. I will not go into details but only highlight a few key points.

5. There has been some slowing down of growth in 1989-90. GDP is expected to rise by 4 to 4.5 per cent, industrial output by about 6 per cent and agricultural output by 1 per cent or so on the peak level reached in the previous year.

6. The price rise this year affects several commodity groups and the pressure of inflation is clearly linked to the fiscal imbalance. The budget deficit and money supply growth have been running well above target. The Revised Estimates for 1989-90, which I will present a little later, indicate that the budget deficit is expected to be substantially higher than Rs. 7337 crores projected in the budget estimates for 1989-90. The growth rate of aggregate monetary resources was 16.5 per cent from the beginning of the financial year to 23rd February, 1990.

7. As regards the trade performance this year, exports have grown at the rate of 38 per cent and imports at 21 per cent in rupee terms in the first nine months of the year. But the pressure on reserves continues as the improvement on trade account is not sufficient to counter-balance the increase in debt-service obligations.

8. I have drawn attention to these features in order to highlight the constraints within which the new Government has to look for ways of fulfilling its mandate.

9. The first task of the new Government was to contain the rise in prices. A Cabinet Committee on Prices was formed and effective steps were taken to increase the supply of essential commodities, break the inflationary psychology and contain inflation. The price situation however, remains a matter for concern and the management of inflation is one of the priority areas for this Government.

10. Adequate stocks of foodgrains are essential for maintaining price stability and our economic security. The Government has given a high priority to stepping up procurement efforts and to rebuilding of stocks. As a result, the procurement of rice has touched a new high of about 10 million tonnes already. Foodgrains stocks in the central pool have been augmented and stand at 11.67 million tonnes at the beginning of February compared to 8.34 million tonnes at the same time last year. Special attention has been given to increasing supplies of essential commodities and streamlining the Public Distribution System. Market intervention operations are being undertaken to stabilise open market prices of some sensitive commodities.

11. Another major problem before the country is the strain on our balance of payments position. In the last few years, large trade and current account deficits have been financed through depletion of foreign exchange reserves and growing recourse to foreign borrowings. To combat the pressures on the balance of payments and to ensure a viable situation over the Eighth Plan period, exports must command the highest priority. The alternative of higher foreign borrowing to finance our essential import requirements runs the risk of mortgaging our hard won economic independence. This is clearly unacceptable. Therefore, the new Import Export Policy 1990-93, to be announced on 1-4-1990, will accord top priority to exports and will give special encouragement for exports which earn high net foreign exchange. The priority for exports will also be reflected in our industrial policy and later I will outline some fiscal measures to promote export production.

12. Our import bill for bulk items is increasing rapidly. The oil consumption, for example, has been rising at the rate of around 8 per cent in the recent past. There has been a huge outflow of foreign exchange on this account. India's foreign debt has been doubled in the last five years. This has added to our vulnerability. The trend has to be reversed. I am convinced that our people will make any sacrifice and meet any challenge in order to preserve our economic independence and spirit of self-reliance. We are ready to go through a period of austerity and hardship in order to avoid excessive foreign borrowings.

13. The fiscal imbalance is the root cause of the twin problems of inflation and the difficult balance of payments position. One of the targets of the Seventh Five Year Plan which was over achieved was deficit financing. While the projected deficit in the 7th Plan period was Rs. 1400 crores, in reality it was more than double.

14. The management of the deficit will require the containment of expenditure growth. I can assure the House that we will spare no effort to reduce the burden of administrative expenditure. But the restraint of expenditure also requires careful consideration of other areas of public spending which involve implicit or explicit subsidies. We have to ask ourselves whether these subsidies are really reaching the people they are meant to serve or whether there is a better way of providing the same benefit.

15. On the revenue side, the real issue is of tax compliance. Tax evasion is rampant. This generates black money and has other serious adverse effects on the economy, such as fuelling inflation and conspicuous consumption. Black money is also generated by shortages, artificially pegged prices and detailed physical controls. The "leakages" from public expenditure programmes also causes serious distortions in the economic and social structure of our society.

16. We will launch a sustained and multi-pronged drive against proliferation of black money which is a social sin and an economic evil. To improve tax compliance, we shall combine reasonable tax rates and simpler tax laws with effective tax administration and strong deterrents against evasion. The Revenue Department is being instructed to pay special attention to vulgar display of ill-gotten wealth, particularly on occasions, such as wedding receptions. We will come down with a heavy hand on those who give vent to their pomp and money power, by circumventing our law, and frittering away the scarce resources of the nation. The Economic Intelligence Bureau is being revamped to coordinate action against tax evaders and black money operators. The Act on "benami" transactions will be recast to make it more difficult for economic offenders to hold wealth in "benami" forms.

17. Administrative curbs against black money must be backed by economic measures. We must reduce the scope of discretionary powers which provide sustenance to black money. Our economic policies will place greater reliance on general, non-discretionary, fiscal and financial instruments and will reduce the role of ad hoc discretionary physical controls.

18. I have also received some suggestions from Honourable Members and fiscal experts on incentive scheme for "uncaring" of black money and channelling it into desired directions. The advantage claimed for such schemes is that, instead of being used for conspicuous consumption or unproductive investment, the unaccounted money can be diverted to create jobs or to serve some other socially useful purpose. The disadvantage is that these schemes generally provide for a more concessional tax treatment of the black money than the rates normally applicable. The different schemes tried out in the past did not yield much and were open to misuse. Human ingenuity manifests itself in strange ways. In the past, it found expression in converting the bearer bonds, issued with the laudable objective of bringing out black money, into alternate currency that exchanged hands at a premium. Thus the instrument to render black money white was itself used with vengeance to reconvert white money into black.

19. Nevertheless, in the present situation, when our needs are large and resources are tight, there is perhaps a case for introducing a time-bound scheme which would permit undeclared incomes and hidden wealth to be used for one or more social purposes, such as, slum clearance, building of houses for lower and middle income groups, and setting up of specific agro-base industries in rural/backward areas. Subject to certain conditions, the source of monies declared under this scheme need not be questioned. There could be a suitable flat rate of tax on such income.

20. The Government would like to have a thorough debate in the Parliament before introducing a scheme of this type. I would very much welcome the views of the Honourable Members during the budget debate. In the light of these discussions the Government will take the final decision.

21. Domestic trade in gold is regulated under the Gold Control Act which was introduced in 1963 with the broad objective of curbing the demand for gold. The Act has been largely ineffective. It has also caused hardship and harassment to small goldsmiths. There is not much point in continuing with such an ineffective legislation. The Government, therefore, proposes to abolish the Gold Control Act. This step would benefit many artisans and small goldsmiths all over the country. At the same time, we will use the Customs Act more vigorously to prevent smuggling of gold.

22. Let me now turn to some issues of long-term development.

23. In the traditional growth pattern, while the poor at the grass root level suffered in silence without direct benefit of growth trickling down to them, the affluent at the top lived in splendid isolation and monopolised most of the gains of economic growth. The new Government rejects this trickle down theory of development. Instead, it would work for growth with equity ensured through employment-oriented planning in which the decentralised institutions of the four pillars state, aptly described by Dr. Ram Manohar Lohia as the 'Choudhamba Raj' will play a pivotal role.

24. Our first priority is employment. In the eighties, our economy grew at around 5 per cent or more. But, according to a recent report of the National Sample Survey the number of persons who are chronically unemployed increased from 8 million in 1983 to 12 million in 1987-88. In addition, there are a vast number who are underemployed and whose earnings from work fall well short of a decent minimum. We believe that 'every citizen has the right to productive and gainful work in order to live meaningfully and with dignity'. We would like to introduce an Employment Guarantee Scheme. However, the cost of doing so in all parts of the country are huge, and we do not have the necessary resources at this juncture. Nevertheless, it is proposed to make a beginning on an Employment Guarantee Scheme for the drought prone areas and areas with an acute problem of rural unemployment. The allocation for the employment schemes of the Department of Rural Development will be supplemented, to the extent feasible, during the course of the year.

25. Faster growth of agriculture must be an important part of this strategy. We have achieved impressive growth in yields in the areas of good irrigation but yields remain very low in large parts of the country which are rainfed or semi-arid. Our strategy for agricultural development must focus on increasing output in these areas through greater investment in irrigation, land development, and soil and moisture conservation. These investments will increase production. They will also generate greater absorption of labour in agriculture. Parallel to this effort, regions of high productivity should aim at diversification of agriculture and development of agro-based processing industries. This will provide the economic linkages between the rural economy and growing markets in urban areas, as well as potential markets abroad.

26. The country had adopted an Industrial Policy Resolution in 1956, which through the years, has governed our broad strategy for industrial development. It is surprising that there is no similar Agricultural Policy Resolution. This Government will remove this lacuna. We will lay the basic foundations of agricultural development through the adoption of an Agricultural Policy Resolution. This will represent our national commitment in respect of a sector which is the hub of our economy. We invite all sections of the people to interact with the Government on the formulation of this Policy Resolution.

27. We are committed to ensuring that 50 per cent of the investible resources are deployed for the development of agriculture and rural development. We have made a beginning, in this year's Central Plan in which the share of the rural sector in budgetary support for the Central Plan will go up from 44 per cent in 1989-90 to 49 per cent in 1990-91. In addition, on the non-Plan side we are providing Rs. 1000 crores for debt relief, and Rs. 4000 crores for the fertilizer subsidy, which also go to benefit rural areas.

28. The steps for the inclusion of the land reforms legislation in the Ninth Schedule of the Constitution have already been initiated and the necessary constitutional amendment will be introduced. Simultaneously, various measures for the restructuring of the land relations are being worked out and we hope to initiate steps in this direction after due consultation with the State Governments.

29. Over the years, poor farmers, artisans and weavers have accumulated debt which they are unable to repay. They have been caught up in a vicious cycle of indebtedness and low incomes which keeps them in perennial poverty. In order to relieve our farmers from the burden of debt, an assurance was given in the National Front's manifesto that relief will

be provided to farmers with loans upto Rs. 10,000 as on 2nd October, 1989. I am glad to inform the House that we are now ready with the scheme of implementation of debt relief to fulfil the promise, and redeem the pledge given to the kisans and artisans.

30. It is proposed to introduce a scheme for providing debt relief which will have the following features. The relief will be available to borrowers who have taken loans upto Rs. 10,000 from public sector banks and Regional Rural Banks. The relief will cover all overdues as on 2nd October, 1989 including short-term as well as term loans. There will be no limit on the size of the borrower's land holdings. However wilful defaulters, who in the past did not repay loans despite own capacity to do so, will be excluded. The Central Government will compensate the public sector banks and Regional Rural Banks suitably for the debts which are thus written off. Many of those who filed insolvency petitions and had taken loans below Rs. 10,000 which were overdue as of 2nd October, 1989 will also be covered under the scheme.

31. The State Governments may also wish to introduce a scheme on the same lines in respect of cooperative banks within their purview. Subject to the constraint of resources, the Central Government will consider suggestions for helping State Governments in implementing a debt relief scheme on the same pattern in respect of cooperative credit institutions under their control.

32. I consider the debt relief measure as a positive step which will enable our farmers, artisans and weavers to increase their productivity. It is at the same time necessary to ensure that there is no erosion of the credibility of the banking system. Once the past over-dues are cleared, it is reasonable to expect that loans taken for current operations will be serviced promptly. The Scheme should contribute to better agricultural recoveries and better identification of wilful defaulters, who do not deserve any sympathy. Banks are being asked to set up a system of maintaining a proper credit history of their borrowers covered under the Scheme. The Government would also like to make it clear that the Scheme will not be extended nor will it be repeated.

33. The Government proposes to introduce changes in the formula for computing costs of production of agricultural crops for price fixation so as to take full account of all costs. In particular the formula will take into account:

- (1) valuation of labour (including family labour) on the basis of statutory minimum wage, or actual wage, whichever is higher,
- (2) the remuneration for the managerial and entrepreneurial efforts of the farmer,
- (3) adjustment of procurement/support prices for the escalation in input costs between the announcement of the prices and the arrival of the crop in the market.

The new formula will be reflected in the procurement support prices to be announced for the next kharif season. As procurement prices are revised in line with costs, the revision of issue prices is also unavoidable. In future, the Government will announce revision in procurement and issue prices at the same time even though these may take effect on different dates.

34. The threat to our environment can no more be ignored. It has been estimated that around 130 million hectares of land is degraded through soil erosion, salinity, total loss of tree cover, etc. Our forests are under pressure from a variety of sources. In urban areas, air and water pollution from industry, transport and other sources is widespread. A healthy environment is part of the quality of life and a productive environment is the basis for development. Our emphasis on rural development and decentralisation will allow us to integrate environmental considerations into the design of development.

35. Let me now turn to another area of great concern—that of unemployed youth. All of us who travel in our constituencies have seen the plight of young people able and willing to work, but unable to find employment. A long-term solution to this problem has to come from a shift to a more employment-oriented growth strategy. But as an immediate step we have decided to give a boost to measure which will assist the youth of this country to acquire the skills that will improve their prospects for gainful employment. A comprehensive Vocational Training Project has been taken up covering 28 States and Union Territories. The Project will improve the quality of craftsmen training, apprenticeship training and advanced training of industrial workers. We also propose to link training and the provision of credit support for self-employment.

36. Under the leadership of Dr. B. R. Ambedkar thousands belonging to the Scheduled Castes had embraced Buddhist religion in 1956 to seek liberation from caste oppression to which they were subjected for centuries. However, in the eyes of the orthodoxy the social stigma on the Scheduled Castes was not erased even after their conversion to Buddhism. It has, therefore, been decided by the Union Government that all the facilities and privileges that were available to the Scheduled Castes will be available to them from the Union Government even after their conversion to Buddhism.

37. A strategy for greater absorption of labour in agriculture has to go hand in hand with faster growth of industry and balanced development of infrastructure, specially power and transport. It is self evident that higher investment and faster growth in incomes in agriculture can be sustained only if industrial production increases to meet the rising demand for inputs and wage goods in particular. This Government will give priority to accelerating industrial growth in a competitive and non-monopolistic environment. The Government will review and simplify the Industrial Licensing Policy to ensure that licensing does not become an instrument for preventing competition and perpetuating monopolies.

38. The Khadi, Village and Small scale sector has a special role to play in any strategy for employment-oriented industrial development. We will work for the harmonious development of cottage, small and large industries and give protection against encroachment of large scale on small scale and small scale against cottage wherever necessary.

39. The withdrawal of the 15 per cent Central Investment Subsidy for Backward Areas has affected the growth of small scale industries. We must take industry to the people and not people to the industry. We propose to reintroduce a Central Investment Subsidy for small scale units in rural areas and backward regions.

40. A major problem faced by small industries is delay in the settlement of bills by large units. The provision of factoring services in which the task of realisation of the bill is taken on by an intermediary is one way of mitigating this. The House will be glad to know that some steps towards this end have already been taken by the Reserve Bank of India.

41. The problems of women entrepreneurs in the cottage and small sector are of particular concern to us. The provisions regarding margin money and seed capital for women entrepreneurs will be reexamined and liberalised.

42. There is a single window scheme for grant of working capital along with term assistance to new projects in the small scale sector by State Financial Corporations. This arrangement facilitates setting up of small scale units without waiting for finalisation of working capital limits from banks. The present limits of project cost for determining eligibility for such composite loans is being raised from Rs. 5 lakhs to Rs. 10 lakhs.

43. Reserve Bank has issued guidelines for provision of credit and rehabilitation of viable small scale units. These guidelines, are intended to assist the small scale sector and not create hurdles in its path. Banks are being asked to implement them faithfully.

44. The public sector is vital to our country's development. It has played a major role in broadening the base for industrial and technological development in this country. The overall working results for the first six months of this financial year show a significant improvement in net profit from Rs. 694 crores last year to Rs. 1103 crores this year. In 1990-91, Central sector enterprises will finance 46 per cent of their plan investment from internal resources. We are committed to making the public sector more efficient and result-oriented so that it can generate more surpluses which can be ploughed back for development.

45. The health of the public enterprises depends crucially on the commitment of its employees and their full participation in management. It has been suggested that one way of securing this is to give workers a share in ownership either through stock option schemes or sale of shares to workers or to trusts owned by workers. Since the equity of public enterprises is not quoted in the market, arrangements will have to be worked out to determine the sale and purchase price of such worker's shares. I invite suggestions from Honourable Members on the merits of this idea and how it could be implemented.

46. We are also firmly committed to the healthy development of capital markets, and to strengthen the role of public financial institutions. The institutions will be given functional autonomy. However they must also be accountable for their actions. The institutions will not be party to corporate battles and clandestine takeovers. The government would like to create an atmosphere and a culture where financial institutions can function objectively without fear or favour.

47. There has been some concern about the role of financial institutions in relation to their intervention in the capital market. I have asked these institutions to frame suitable guidelines so that their actions are not only objective but seen to be so. Each financial institution is expected to operate in the interest of its depositors and investors consistent with national priorities. There may be occasions when there is an abnormal and persistent upward or downward movement in share prices because of concerted bull or bear pressures. In such situations, the financial institutions, will play a stabilising role in the capital market.

48. The growth of banking since nationalisation has been phenomenal. The banking system has been extended to the remotest part of our country. Banks are now playing a vital role in mobilising peoples' savings and channelling them into productive areas. At the time of nationalisation, only 14 per cent of the bank credit was provided for the priority sector covering sections, such as, agriculture, rural development and small industries and businesses. Today, this proportion is nearly 45 per cent. This is the measure of the success of nationalisation.

49. There is one aspect of banking operations which is of concern to me. This is the low credit deposit ratio in some regions. A variety of factors determine this ratio. I have asked the Reserve Bank of India to pay special attention to this problem and further improve credit delivery in such areas consistent with financial discipline.

50. Our bank managers and employees are, as a group, the most qualified, dedicated and hard working. But it is also a fact that the level of public satisfaction with the banking services is not as high as it should be. Over the years, perhaps some structural rigidities have crept in. These need to be removed. There is need for greater competition and greater operational flexibility in respect of banking services. The banking culture has to be made more responsive to the needs of the public. I am requesting the Reserve Bank of India to set up a Committee of Bankers, bank employees, depositors and borrowers to consider these aspects and make recommendations to the Government.

51. The previous Government had announced the formation of the Securities Exchange Board of India (SEBI) in 1987. Three years have passed and the legislation for giving statutory authority to SEBI has not been introduced. We will ensure that this is done in this budget session.



52. Science and technology is the mainspring of development. We are proud of the capabilities that we have built up in critical areas like agriculture, space research, atomic energy and defence. We will aim at utilising the talent of our scientists and engineers towards two basic ends :

- the development of appropriate technologies for agriculture, non-conventional and renewable energy and other employment intensive activities;
- the establishment of a strong base of self reliance in critical areas of modern technology.

Public spending on R & D, incentives for the use of indigenous technologies and policies to guide private research efforts will be oriented towards these objectives.

53. There is a large community of Indians settled abroad. They have achieved tremendous success in their chosen professions and occupations. True to the rich tradition of our ancient culture, their physical location has not weakened the strong intellectual, philosophical and social links that they have with the country of their origin. The Government will continue to provide special facilities for them to invest their savings in this country. The procedures will be simplified so that they can function with a sense of confidence and in line with declared national policy.

54. Let me now turn to the Revised Estimates for 1989-90 and the Budget Estimates for 1990-91.

#### REVISED ESTIMATES FOR 1989-90

55. Revised Estimates of Expenditure for the current year show an increase of Rs. 5620 crores over the Budget Estimates. Of this, Rs. 4958 crores are on non-Plan account and Rs. 662 crores on Plan account.

56. Honourable Members are aware of the strains on our security environment which unfortunately coincide with the strains on our economy. Hence, on the non Plan side, Defence Services are being provided additional Rs. 1500 crores to meet their essential requirements and committed expenditure. The provision for fertilizer subsidy will be Rs. 950 crores more mainly due to larger imports and clearance of arrears claims. There is an increase of Rs. 275 crores in food subsidy, mainly for clearing arrears due to Food Corporation of India. An additional provision of Rs. 468 crores has been made for export promotion and market development. Interest payments will be Rs. 710 crores higher. The Government is of the view that the amount of compensation to be paid to the victims of the Bhopal Gas tragedy under Court order is too meagre for the magnitude of sufferings of these innocent people. The matter is under review in Court and in the meantime Government have decided to pay interim relief for the victims for which a provision of Rs. 230 crores has been made which, inclusive of bank interest over a period of 3 years, will amount to Rs. 360 crores. The increases are partly offset by savings in some areas notably in the lump sum provision made for dearness allowance consequent on transfer of liability on this account to the budget of the Ministries/Departments.

57. On the Receipt side, while collection from Corporation Tax and Customs duties are expected to more or less reach Budget estimates, the receipts from Union excise duties are estimated to be Rs. 799 crores less than the budget. Income tax collections, on the other hand are expected to be more by Rs. 755 crores. States' share of taxes including the sum payable to States on the basis of collection figures certified by the C&A for the earlier years are placed at Rs. 1222 crores against Rs. 12438 crores at the budget stage, i.e. Rs. 704 crores more. The shortfall in net revenue receipts is expected to be more than off set by larger receipts from small savings, provident fund collections and special deposits of non-government provident funds, etc.

58. The overall deficit for the current year is now estimated at Rs. 11750 crores against the budget estimate of Rs. 7337 crores.

#### Budget Estimates for 1990-91

59. The next financial year is the beginning of the Eighth Five Year Plan. This Government is irrevocably committed to planned economic development, and to making the plan more meaningful to the people. As a part of the new strategy, in the next years Plan, we have provided more for those programmes and schemes which benefit the people directly. We have favoured those programmes that create more jobs, generate self-employment opportunities, improve the living environment in our village and strengthen our agriculture. This is the surest route to overcome poverty. An increase of 31.7 per cent on last year's budget estimate is being provided for Agriculture and Allied Services, without taking into account the budget provision of Rs. 1000 crores for the debt relief for farmers, weavers and artisans. The allocation for anti-poverty programmes, which are spread over different budget heads is being increased by about 23 per cent over last year's budget estimate. This includes the outlay for employment programmes in rural and urban areas which is being increased by 30 per cent on last year's budget estimate.

60. We have a firm commitment to accord highest priority to agriculture and rural development and our thrust and actions are in conformity with that commitment.

61. For the Central Plan 1990-91, I propose an outlay of Rs. 39,329 crores—an increase of Rs. 4,883 crores or 14.2 per cent over the current year's outlay. Of this, Rs. 17,344 crores will be provided as budgetary support and the balance of Rs. 21,985 crores will be subsidised by the public sector enterprises through their internal resources, as well as borrowings.

62. For the year 1990-91, an outlay of Rs. 905 crores is proposed for the Department of Agriculture and Cooperation which represents an increase of 17.5 per cent over the budget estimates for the current year. In addition, I am also proposing an outlay of Rs. 155 crores for Agricultural Research and Education compared to the provision of Rs. 116 crores in 1989-90—an increase of 41 per cent.

63. I have already referred to the intention of the Government to make a beginning in respect of an Employment Guarantee Scheme. The Annual Plan outlay proposed for the Department of Rural Development is Rs. 3,115 crores. It is my intention to provide some additional funds, within the constraint of resources, to enable an Employment Guarantee Scheme to be introduced in selected areas.

64. The Government is pledged to securing a fair deal for the most oppressed, exploited and deprived sectors of the society, namely, the Scheduled Castes, and Scheduled Tribes. It is proposed to make a provision of Rs. 320 crores for the schemes for Scheduled Caste, and Scheduled Tribes in the Annual Plan 1990-91 as against Rs. 269 crores in 1989-90 BE. The Special Central Assistant to Social Component Plans of Tribal Sub Plans of States, has also been increased.

65. The Government would intensify the efforts for eradication of illiteracy. The very fact that millions of voters in the country have to identify the names of candidates on the ballot papers only from the election symbols is itself a symbol of the extent of illiteracy. We have made 25 per cent increase in allocation for National Literacy Mission. Special attention to vocational programmes at all levels will be given. The process of modernisation of technical education, and support to thrust and frontier areas in science and technology will be maintained. I am proposing an outlay of Rs. 865 crores for the Department of Education during 1990-91.



services, special attention will be paid to the needs of the rural people. I am proposing an outlay of Rs. 950 crores for the Ministry of Health and Family Welfare for 1990-91.

67. The Government attaches great significance to the welfare of the weak, the poor and the deprived living in the urban areas. Major initiatives for employment, low cost sanitation for liberation of scavengers and provision for night shelters are proposed to be launched. The plan outlay of the Urban Development Sector is being increased to Rs. 272 crores in 1990-91 from Rs. 89 crores in 1989-90 BE for this purpose.

68. The Annual Plan outlays for 1990-91 for the infrastructure sectors are proposed to be stepped up. The outlays for Petroleum and Natural Gas is proposed to be increased by 18.6 per cent, Railways by 12.4 per cent and Power by about 10 per cent.

69. The details regarding Central Plan outlays for these and other sectors are in the Budget documents. I do not wish to take the time of the House in making my speech a substitute for the voluminous budget documents, and thus deprive the Members of the excitement of reading these documents.

70. Honourable Members will be happy to know that the Central assistance for State and UT Plans next year will be Rs. 12,848 crores, including the Plan revenue grants recommended by the Finance Commission as against Rs. 10,450 crores excluding drought assistance provided in Budget Estimates for the current year. This represents a substantial step up of 22.9 per cent.

71. Budget Estimates for the next year provide Rs. 64,515 crores for non-Plan expenditure as against Rs. 59,220 crores in Revised Estimates for the current year. The main increase next year is under interest payments provision for which goes up from Rs. 17,710 crores this year to Rs. 20,850 crores next year.

72. The Government have appointed a Committee to consider the issue of One Rank One Pension in all its aspects. The Report of the Committee is expected by end of March, 1990 and Government will take further action thereafter.

73. For Defence Services, a provision of Rs. 15,750 crores has been made in the Budget Estimates. This increase in the defence expenditure is not of our choice. It is the direct result of the situation on our borders.

74. Freedom struggle is indivisible and therefore it has been decided that those who fought for Goa's liberation from the Portuguese rule will be eligible for Union Government's pension and all other benefits available to other freedom fighters.

75. The Ninth Finance Commission has submitted its second report covering the period 1990-95, a copy of which was laid on the Table of the House last week along with a statement of decisions of Government on the recommendations. These have been taken into account while framing the Budget for next year. The recommendations of the Finance Commission accepted by Government will cast an additional burden of the order of Rs. 773 crores on the Central Budget in 1990-91.

76. Government are alive to the important issue of checking proliferation of Government expenditure especially in non-priority and non-developmental areas. I am requesting all the Ministries and Departments to absorb the liabilities on account of additional instalments of D.A. which will be payable next year from within the budget provisions made for them by effecting economies and eliminating non-essential expenditure. I am, therefore, including only a nominal provision of Rs. 100 crores in the next year's budget as lump sum provision for D.A. This is mainly to meet the possible requirements of small Departments with limited budgets who may not find it possible to absorb D.A. increases to the full extent.

809 GI/90—4

77. On the Receipts side, Gross Tax Revenue at the 1989-90 rate of taxation is estimated at Rs. 57988 crores and the net tax revenue after payment to States of their share of taxes is placed at Rs. 43507 compared to Rs. 37798 crores in the Revised Estimates for the current year.

78. I have taken a credit of Rs. 8000 crores on account of market borrowings as against Rs. 7,400 crores in the current year. External assistance net of repayment is expected to be of the order of Rs. 4327 crores in the next year as against Rs. 3901 crores in the current year. Taking into account the other variations in receipts and expenditure the overall deficit for next year at the 1989-90 rate of taxation is estimated at Rs. 9165 crores.

## PART B

79. Having taxed your patience so far, now let me turn to other areas of taxation and reliefs for which you must have been waiting impatiently. Let me begin with my proposal in respect of direct taxes. I am introducing certain major changes in the rate structure for personal income-tax with a view to providing relief to low and middle income groups, and to make the saving linked incentives more equitable for tax payers in different income slabs. My first proposal to raise the exemption limit is in fulfilment of a promise made in the National Front manifesto. I am raising the exemption limit for personal income taxation from Rs. 18,000 to Rs. 22,000. Roughly, one million persons will go out of the tax net as a result of this change. In deciding the new limit, I have had to balance two conflicting considerations. On the one hand, it is a fact that the lower income groups have been affected the most by price rise, and there is a case to raise the exemption limit. On the other hand, an increase in the limit narrows the tax base and involves substantial loss of revenue as the benefit of the increase is spread over all taxpayers, and is not confined to the lower end of the income levels. Experts have often argued that keeping in view our per capita income, raising of the exemption limit is not justified. However, as I temperamentally prefer to avoid taking extreme positions, I have chosen the middle course which I believe is fair and reasonable.

80. As further measure of relief to the lower and middle income groups, I am extending the lowest rate of 20 per cent from the present limit of Rs. 25,000 to Rs. 30,000.

81. Last year, a surcharge at the rate of 8 per cent was introduced for financing employment programmes. Dropping this employment surcharge would have brought into question my irrevocable commitment to employment oriented planning. I, therefore, have no choice but to continue this surcharge. This will now be applicable beyond taxable income of Rs. 75,000 as against the present limit of Rs. 50,000.

82. As the Honourable Members are aware, the existing schemes of tax incentive to promote savings are based on deductions from income. A person gets tax relief at the highest marginal rate of tax applicable to him. Accordingly, it confers higher amount of tax benefit to a person with higher income vis-a-vis a person with a lower income. With a view to removing this inequity, I propose to introduce a system of tax rebate on the gross amount of savings under section 80C. Under the new system, a person contributing to provident fund, life insurance, National Savings Certificates, etc. as earlier, will now be entitled to a tax rebate calculated at the rate of 20 per cent on such savings. The maximum tax rebate allowable will be Rs. 10,000 generally and Rs. 14,000 in the case of authors, playwrights, artists, musicians, actors, sportsmen and athletes. This is broadly equivalent to the maximum relief available now. All persons will get the same amount of tax benefit on a given amount of savings, irrespective of their levels of income. The low income taxpayer will benefit.

83. Let me illustrate the impact of the above proposals. A person with a salary income of Rs. 3,500 per month i.e. Rs. 42,000 per year, who saves Rs. 8,000 per year in provident fund and insurance presently pays Rs. 1,000 net year as tax. Under the new dispensation, he will not have to pay any tax at all. The upper income group will have to save Rs. 50,000 to get the full relief of Rs. 10,000. Under the old system they would have got the same relief by saving only Rs. 39,500. I may mention in passing that the new system of a uniform tax rebate will also lead to a substantial simplification in tax deduction at source by employers.

84. As a further incentive to save, I propose to increase the limit available for the savings incentives under section 80CCA from Rs. 30,000 to Rs. 40,000. Since the savings under this are on a 'netting' principle and are added back to income when withdrawn, the present system of deduction from taxable income will continue.

85. In addition to this, the Equity Linked Savings Scheme (ELSS) announced last year has now been finalised on a 'netting' principle. Investment in units under the Scheme will be eligible for deduction upto a maximum of Rs. 10,000 from the total income. The annual return on the investment in the units will be eligible for tax concessions under section 80L. On repurchase of the units by the Mutual Funds the capital amount representing the cost of the units will be taxed as income in the year of repurchase and the excess will be liable to tax as capital gains. The Equity Linked Savings Scheme will eventually replace the present deduction under section 80CC. Meanwhile, this provision is being extended for investments made upto 31st March, 1991.

86. In an effort to mitigate in some small measure, the hardship of parents or guardians of physically handicapped or mentally retarded persons with incomes upto Rupees sixty thousand per annum, I propose allowing a deduction of Rs. 6,000 from the parents or guardians total income to cover expenses on medical treatment, training and rehabilitation of such persons.

87. I propose to increase the deduction in respect of professional income from foreign sources, available to authors, playwrights, artists, musicians, actors and sportsmen, including athletes from the existing rate of 25 per cent to 50 per cent of the income or 75 per cent of the foreign exchange brought into India, whichever is higher. In the case of professors, teachers and research workers also, the present provision has been liberalised to allow deduction of 75 per cent of the foreign exchange brought into India.

88. I will now make my proposal in regard to corporate taxation. The corporate sector has often claimed that the rate of Corporate Tax is high and that this inhibits growth as well as tax compliance. On clear scrutiny, I find that the rate is only seemingly high, because the system provides too many exemptions. After all the admissible exemptions and deductions, the effective rate falls drastically. Many large and high profit making companies had been able to escape the tax net and were paying zero tax for a long time. That is why the contribution of the corporate sector to tax revenue was not commensurate with the profits they earned; nor with the needs of national development. The tax system also tilted the balance in favour of capital intensive production.

89. To ensure better tax compliance I propose a twin strategy. I am abolishing major incentives like Investment Allowance and Investment Deposit Account with a view to closing the escape route for the corporate sector to go out of the tax net, and having closed that route I propose to fix the tax rate for widely held domestic companies at 40 per cent with corresponding changes in rates for other

domestic companies. This twin strategy will raise the effective tax rate and will also give substantial additional revenue of Rs. 800 crores.

90. The only major deductions that will now be permitted are those relating to foreign exchange earnings and for setting up new industrial undertakings. The deduction for setting up new industries is being raised from 25 per cent to 30 per cent in the case of companies and from 20 per cent to 25 per cent for others. The period during which the benefit can be availed of is being extended from 8 to 10 years.

91. With the abolition of the major exemptions, there is a case for also removing the special provision regarding tax on minimum profits contained in section 115J of the income-tax Act. Accordingly, I propose to discontinue that provision with effect from the assessment year 1991-92.

92. I am also introducing an important change in the taxation of inter-corporate dividends. At present 60 per cent of the dividend income received by a domestic company from another is exempt from tax. There is a tendency towards holding of personal wealth in the form of companies which are in effect closely-held. In order to encourage genuine investment activity while at the same time discouraging the use of corporate framework for holding personal wealth, I propose to exempt dividends received by domestic companies from other domestic companies to the full extent to which they themselves declare dividend during the relevant period. However scheduled banks and public financial institutions would, in substance, continue to be governed by the provisions of section 80M as they presently stand.

93. The result of the reform of the corporate tax system proposed by me will be to increase the buoyancy, simplify the tax structure and make it neutral as between small and large companies. At the same time, it will provide strong incentive for export and for investment in new industrial undertakings.

94. Many small scale industries are organised as partnerships. I propose to raise their exemption limit from Rs. 10,000 to Rs. 15,000 and to lower the tax rates suitably.

95. Restoration of ecologically degraded areas fulfils the objectives of employment generation, enhances the supply of fuel wood and fodder and also contributes to the overall social, economic and environmental stability of the rural areas. In order to promote afforestation, I propose to extend the provision of section 35CCB and section 80GGA to taxpayers who contribute to a fund or programme for afforestation approved by the prescribed authority.

96. As in the case of personal income tax, I propose to continue the existing surcharge of 8 per cent on corporate taxpayers also on all incomes above Rs. 75,000.

97. I also propose to make a major change in the taxation of gifts. At present gifts are taxed in the hands of the donor, but there is no limit on the amount which a donee can show as having been received by way of gifts. Because of this, the mechanism of gifts is used to split up capital and launder black money. Some instances have also come to notice recently where attempts have been made to explain away wasteful and ostentatious expenditure on marriage receptions and other functions as having been financed out of gifts. With a view to curbing such practices, I have decided to substitute the present gift-tax on donors with a donee based gift-tax. Any person, who claims his assets or his expenditures as having been financed from gifts will now be liable to a gift-tax on a graduated scale. Thus he will have the pleasure of transferring a part of his bounty as a gift to the exchequer.

98. The primary purpose of the donee-based gift-tax is not to raise revenue but to check tax evasion and conspicuous consumption. In order to take care of legitimate gifts there will be basic exemption limit of Rs. 20,000 per year. In the case of total gifts exceeding Rs. 20,000 but not exceeding Rs. 50,000, gift-tax will be levied at 20 per cent; for total gifts exceeding Rs. 50,000 but not exceeding Rs. 2,00,000 at 30 per cent; and for total gifts exceeding Rs. 2,00,000 at 40 per cent. In addition, I also propose to allow for a substantially higher limit of rupees one lakh for gifts received from all sources by an individual at the time of marriage. Further, gifts received in foreign exchange through official channels will also be exempt.

99. I propose to make the new system applicable in respect of gifts made on or after 20th March, 1990. Consequently, the existing Gift Tax Act taxing the gifts in the hands of donors will cease to be operative in respect of gifts made on or after that date.

100. Legislation to give effect to this new scheme is proposed to be introduced during the current session of Parliament.

101. I do not propose to take up the time of the House with other minor changes in the Direct Tax Laws.

102. As I mentioned earlier, there will be a gain in revenue from corporate tax to the extent of Rs. 800 crores. The loss in revenue from income-tax other than corporate tax after providing for better compliance is expected to be Rs. 250 crores. There will, therefore, be an additional accrual of Rs. 550 crores in respect of direct taxes.

103. Sir, I shall now deal with my proposals relating to indirect taxes. The main thrust of the proposals is on simplification and rationalisation. Simultaneously I have also attempted to mobilise some resources in a manner that does not hurt the common man and at the same time helps to curb elitist consumption. A major emphasis has been on strengthening impulses for growth and exports. Significant changes in duty structure are also proposed to develop a quality culture in our industry. I have also not failed to give relief to the deserving sectors, particularly small scale industry, agriculture and environmental protection. All these measures have been described in some detail in the Explanatory Memorandum to the Finance Bill I shall deal briefly with more important of these proposals.

104. Presently, the import duty rates are widely dispersed. With a view to rationalising the rates and bringing down their multiplicity, the total of the basic and auxiliary duty rates of customs are being placed in a limited number of slots in the range of zero to 125 per cent in respect of most items. Further as a step towards rationalisation and simplification of the Central Excise Tariff, the duty rates are proposed to be recast for a large number of goods. Though as a result of the rationalisation, the duty rates on certain commodities may marginally go up or down, the proposals on the whole are intended to be broadly revenue neutral. The reduction in the number of rates in each Chapter of the Tariff will simplify assessment. It will be our endeavour to ensure a measure of stability for the ad valorem rates.

105. First, I shall take up the proposals which are in the nature of concessions in customs and excise duties.

106. Agriculture is a priority area in our framework of development and tax rates are already kept low on most of the inputs used in this sector. Specified pesticides and pesticides intermediates enjoy concessional rates of import duty of 70 per cent and 60 per cent respectively. I propose to reduce the import duty on a few more specified bulk pesticides and pesticides intermediate to these levels. The proposal involves a revenue loss of about Rs. 16 crores.

107. In order to encourage the use of rape-seed oil and mustard oil, of which there is an abundant production in the country, I propose to completely exempt refined rape-seed oil and mustard oil which are currently attracting excise duty of Rs. 750 per tonne. The revenue loss on account of this proposal is estimated to be Rs. 8 crores.

108. I propose to remove excise duty on pickles altogether in the hope that this will lend some flavour and spice to my budget.

109. Excise duty on coffee is presently levied at the rates Rs. 78 and Rs. 105 per quintal depending upon the variety. As a measure of relief to the coffee growers, I propose to reduce the duty to a uniform level of Rs. 50 per quintal. This concession involves a revenue loss of Rs. 4 crores.

110. Marine products constitute a major thrust area of the country's exports. In order to make imported prawn feed more economical, I propose to reduce the duty on this item to 25 per cent. In order to help modernisation of food processing and sea food industries, I propose to extend the concessional rate of import duty of 40 per cent now available to certain specified machinery, to a few more items.

111. With a view to reducing the cost of cattle feed, I propose to completely exempt molasses used in its manufacture from the whole of excise duty. I also propose to prescribe concessional import duty of 40 per cent in respect of certain items of equipment required in cattle breeding and dairying.

112. I propose to exempt fully foot-valves of certain specifications from excise duty in order to promote efficiency of agricultural pumps.

113. Presently, kraft paper and kraft paper-board used for apple packaging in Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Uttar Pradesh are exempted from excise duty, as a measure to conserve forest wealth. I propose to extend this concession to packaging of all horticultural produce all over the country. This is expected to result in a revenue loss of Rs. 5 crores.

114. I propose to extend full exemption from excise duty to hand made paper and paper board manufactured by units of Khadi and Village Industries Commission even when power is used in the process of sheet forming. I also propose to enhance the value limit for the purposes of excise duty exemption on footwear from Rs. 75 to Rs. 100 per pair in respect of such footwear made by unit under KVIC as well as those run with the assistance of IRDP.

115. In addition to the measures outlined in the earlier part of my speech for the promotion of small scale sector, I also propose to extend some more fiscal concessions to this sector. Presently, small scale unit are allowed complete exemption from excise duty in respect of clearance of goods upto a value of Rs. 15 lakhs in case such goods fall under only one Chapter of the Central Excise Tariff. I propose to increase this value limit to Rs. 20 lakhs. The total exemption available to goods cleared upto a value limit of Rs. 30 lakhs, when such goods fall under more than one Chapter of the Tariff, will remain unchanged. The increase in exemption limit for small scale units involves a revenue loss of Rs. 67 crores. The scheme of notional credit of 5 per cent in the case of inputs manufactured in the small scale sector is also being continued for one more year from the 1st April, 1990. Further, the limit of value of clearance of goods in a financial year for the purpose of obtaining a central excise licence is being increased from the existing level of Rs. 10 lakhs to Rs. 15 lakhs. It has also been decided that the licensed small scale units having value of clearances upto Rs. 20 lakhs in a year will henceforth be required to furnish only quarterly returns of production, clearance and duty payment. These changes are proposed to take effect from the 1st April, 1990.

116. In order to reduce the prices of life saving drugs, I propose to exempt certain finished formulations containing kinamycin, which is an anti-TB drug, from central excise duty. Specified bulk drugs which are required for the manufacture of certain life saving medicines are also being exempted from customs duty. I propose to reduce the import duty on certain specified drug intermediates to 20 per cent. These proposals involve a loss of revenue of nearly Rs. 17 crores.

117. We are all aware of some recent tragedies involving unhygienically packed intravenous fluids. In order that the pharmaceutical industry is encouraged to employ latest techniques of aseptic packing, I propose to reduce the import duty on aseptic form fill seal machines for use by that industry from the present level of 147.5 per cent to 40 per cent.

118. Certain life saving equipments are eligible for complete exemption from import duty. I propose to extend this benefit to certain specified instruments and implants for physically handicapped persons. I propose to give some concessions in customs duty to these aids.

119. I propose to reduce the import duty on homoeopathic medicaments as well as on certain inputs for the manufacture of such medicine. This involves a revenue loss of about Rs. 5 crores.

120. With a view to giving an impetus to industrial production and to boost exports, I propose to grant some concessions to capital goods and machinery.

121. There has been a feeling that our exports are not able to face international competition due to high cost of imported capital equipment. A scheme is being worked out for making available to registered manufacturer-exporters the facility of import of capital goods at concessional rate of duty against suitable export obligation. Broadly, capital goods upto a specified value limit imported under the scheme would be eligible to a concessional import duty of 25 per cent. This will be subject to the condition that goods of a minimum of three times the value of the imported capital goods are exported within four years from the date of importation. The details of this scheme will be announced in the new Import and Export Policy.

122. Concessional import duties have been prescribed from time to time on machinery required for various export thrust sectors. I propose to extend the concession to specified items of machinery for rubber belting industry and forged hand tools industry. The concession involves a revenue loss of Rs. 8 crores.

123. In order to promote investment and strengthening indigenous capital goods sector, I propose to reduce the excise duty on such machinery on a selective basis by 5 per centage points. This concession will lead to loss of revenue to the extent of Rs. 60 crores. I am one of those who believe that the indigenous capital goods sector is integral to our search for self-reliance. I hope, the reduction in excise duty will make our capital equipment more competitive and spur modernisation.

124. With a view to encouraging industrial units to invest in quality upgradation and strengthen quality control, I propose to prescribe a concessional import duty of 40 per cent on specified instruments and equipments. The proposal involves a revenue loss of Rs. 30 crores. This substantial revenue loss is worthwhile in the interest of improving the quality of indigenous products.

125. In the interest of better environmental protection and pollution control, I propose to extend the present concessional customs duty of 40 per cent to some more specified air and water pollution control equipments. At the same time, I propose to reduce the excise duty on certain specified pollution control equipments from 15 per cent to 5 per cent.

126. Heavy investments are required for the upgradation of the facilities available at the airports. I propose, as a measure of relief, to reduce the import duty on navigational, communication, air traffic control and landing equipments imported by the National Airport Authority of India to a level of 25 per cent. The proposal involves a revenue loss of Rs. 7.5 crores.

127. In order to promote establishment of telecommunication network in rural areas, I propose to reduce the excise duty on specified telecommunication equipment from the existing rate of 20 per cent to 15 per cent. This will lead to a revenue loss of Rs. 15 crores.

128. I propose to reduce the excise duty on dry cell batteries from 35 per cent to 30 per cent. The relief will involve a revenue loss of Rs. 10 crores.

129. It has been represented that film industry is facing difficulties on account of video piracy. In order to help combat this menace by simultaneous release of prints in a number of cinema houses, I propose to fully exempt feature films from excise duty. The proposal would involve a revenue loss of Rs. 8 crores. I hope, with this incentive, the films which had gone into slow motion will regain their lost momentum.

130. In order to give relief to the newspaper industry, I propose to reduce the import duty on standard newsprint by Rs. 100 per tonne.

131. As a matter of administrative simplification, I propose to shift the incidence of excise duty from truck body building activity, which is mostly in the unorganised sector, to motor vehicle chassis.

132. Now I move on to a package of proposals relating to the textile industry. These aim mainly at simplifying and rationalising the tariff structure, minimising the scope for evasion and ensuring a lower rate of duty for most varieties of cheaper fabrics. There are essentially two sets of proposals. The first relates to duty rationalisation at the fabric stage and the second to changes in excise and import duties on man-made fibres and yarns as well as the intermediates used to produce them.

133. There is a growing concern about the plight of the handloom weaver. It is widely believed that one of the main causes of the distress is the neutralisation of the tax concessions given to this sector by wide-spread tax evasion at the processing stage. There is thus a near unanimous view in favour of transferring the excise duty from fabrics to yarn, which I share. However, in the case of man-made fabrics, the entire duty is by way of additional excise duty in lieu of sales tax. Therefore, any change in the duty structure can be made only in consultation with the States. I propose to consult the Chief Ministers shortly in this regard.

134. A part of the duty on cotton fabrics is, however, in the shape of basic excise duty. As a first step, I propose to transfer the whole of the basic duty on cotton fabrics to yarn. As the hank yarn used by handlooms will continue to be exempted, the price differential between hank yarn and cone yarn would be widened and this should greatly improve the competitiveness of the handloom sector.

135. Since at present the additional excise duty at the processing stage cannot be shifted to yarn without consultation with the States, I have attempted to rationalise the duty structure on fabrics. The number of slabs in the case of man-made fabrics is being reduced in a manner that the duty on fabrics becomes more equitable and the administration of tax laws more efficient. The rationalisation will also, I believe, greatly reduce evasion and consequently improve realisation.

136. Let me turn to man-made fibres, yarns and the intermediates used to produce them. Honourable members will recall that duties were reduced substantially on man-made textiles in 1985 and 1988. While the incidence of taxes was lowered, there have been complaints that the consumer did not get the corresponding benefit. I have thus tried to revise the duty structure keeping in mind the ability of different sectors to bear the additional burden. This will also help the competitiveness of the handloom sector where the dominant fibre is cotton. The major changes I am proposing are :

- imposition of a basic excise duty of Rs. 4.40 per kg. on PTA and Rs. 3.60 per kg. on DMT which will yield Rs. 80 crores.
- increase in the basic excise duty on polyester filament yarn from around Rs. 50 to Rs. 55 per kg. and on nylon filament yarn from around Rs. 37 to Rs. 50 per kg. yielding additional revenue of Rs. 156 crores,
- increase in the basic excise duty on viscose staple fibre from around Rs. 7 to Rs. 8.50 per kg. leading to a revenue gain of Rs. 15 crores,
- reduction in the basic duty on polyester staple fibre from around Rs. 14 to Rs. 8.50 per kg. involving a revenue loss of Rs. 65 crores; and
- some reduction in the basic duties on various polyester blended yarns.

137. In order to ensure a measure of price discipline in this industry, I propose to reduce import duties.

- on DMT and PTA from 195 per cent to 150 per cent.
- on NFY from 130 per cent to 100 per cent.
- on PFY from 205 per cent to 180 per cent; and
- on VSF from 55 per cent to 40 percent.

The revenue loss from these duty reductions will be marginal since actual imports are not expected to be significant.

138. Keeping in view the sharp decline in the international price of MEG, I propose to raise the import duty on this item from 90 per cent to 150 per cent. This will result in an additional revenue of nearly Rs. 48 crores.

139. Honourable Members may recall that for providing cheap cloth to the weaker sections of the society and to encourage the development of the handloom sector, additional excise duty under Textiles and Textiles Articles Act was levied in 1978. The present rate of this duty is generally 13.64 per cent of the basic excise duty. In addition to this duty, a cess at the rate of 2.5 paise per square metre is levied on fabrics for the purpose of developing khadi and other handloom industries. I propose to merge both these levies by raising the additional duty from 13.64 per cent to 15 per cent of the basic excise duty.

140. There are certain other rationalisation measures relating to textiles including marginal adjustment of duty rates on acrylic fibre, polypropylene staple fibre and filament yarn etc., without significant revenue implications.

141. The jute industry needs encouragement for diversification of its products. I propose to fully exempt jute blankets, floor coverings, matings and bleached, printed and dyed jute fabrics from excise duty. Full exemption available to jute yarn supplied to KVIC units is also being extended to the handicraft sector.

142. I hope, having relished so far the liberal reliefs, the Honourable Members will not now grudge some revenue earning measures.

143. The family members of my smoker friends would, I am sure, be expecting an increase in the rates of excise duty on cigarettes in the interest of the health of the smokers. I will not disappoint them. The increase in duty will be 15 paise for the cheaper cigarettes and 75 paise in the case of costlier cigarettes per packet of ten. There will be no change in the duty rate on non-filter cigarettes of length upto 60 mm. I would hasten to add that I do not propose any change in the excise levy on biris. This measure is estimated to yield additional excise revenue of Rs. 131 crores. I shall be more than happy if my actual collections are much less due to fall in cigarette consumption.

144. Some sympathetic increase in the excise duty rates on pan masala is also being made to yield additional revenue of Rs. 6 crores.

145. I propose to increase the excise duty on cocoa and cocoa preparations from 10 per cent to 15 per cent, on jams, marmalades etc. from 5 per cent to 10 per cent and on ice cream from nil to 10 per cent. The revenue gain from these measures will be of the order of Rs. 26 crores.

146. The House will agree that items used by the affluent sections of the society must bear a higher burden of levies. I propose to increase the excise duty on certain items like microwave oven, washing machine, certain sophisticated varieties of audio systems, video cassette recorder and player, electronic games and relatively high priced cooking ranges.

147. I propose to increase the excise duty on motor cars from 35 per cent to 40 per cent. This measure will yield additional revenue to the tune of Rs. 79 crores. I do not propose to make any change in the excise duty on two wheelers and tractors.

148. The specific duty rates of excise on refrigerators, air-conditioners of capacity upto 1.5 tonnes and automotive gas compressors are being increased. I propose to enhance the excise duty on car air-conditioning parts including those forming the kit from 40 per cent to 65 per cent. These proposals involve a revenue gain of Rs. 14 crores.

149. Tyres and tubes, for a few varieties, are currently subject to central excise levy at specific rates. On these items, owing to recurring increase in prices, the duty incidence in ad valorem terms has come down. As a corrective measure, I propose to raise the existing specific rates on tyres and tubes. However, I do not propose any increase of duty on tractor, trailer and two wheeler tyres and tubes. This, along with certain other rationalisation measures, is likely to yield a revenue gain of about Rs. 40 crores.

150. I propose to raise the specific rates of basic duties of excise on iron and steel. The increase will generally be Rs. 500 per tonne in the case of stainless steel items and Rs. 100 per tonne in the case of other items. In the case of downstream dutiable products, MODVAT credit would continue to be available. The revenue gain from this proposal is of the order of Rs. 104 crores.

151. Presently, the total rate of import duty on most of the stainless steel and articles thereof is 345 per cent. I propose to bring down the rate to the level of 200 per cent. The proposals in regard to customs duties on these and other steel items are expected to result in the loss of revenue to the tune of Rs. 10 crores.

152. At present, the country has a surplus production of aluminium. In order to discourage imports, I propose to increase the basic customs duty on aluminium ingots by Rs. 3500 per tonne.

153. Major plastic raw materials attract excise duty ranging from 30 per cent to 65 per cent. However, the rate of duty on polystyrene is only 20 per cent. As a measure of rationalisation, I propose to increase this rate to 30 per cent. The proposal is expected to yield additional revenue of Rs. 5 crores.

154. I propose to increase the basic excise duty on paste grade PVC used in the manufacture of leather cloth from Rs. 15000 to Rs. 20000 per tonne as an anti-evasion measure. The excise duty rates on PVC coated textiles are also proposed to be revised upwards. These measures are expected to yield Rs. 17.5 crores.

155. At present, various categories of paints and varnishes are liable to excise duty at different rates ranging between 15 per cent and 35 per cent. I propose to rationalise the rates by keeping only two levels of duty at 15 per cent and 30 per cent as against the present five rates. The proposal involves prescribing a uniform excise duty of 15 per cent on insulating varnishes and water based paints and 30 per cent on oil based and plastic based decorative paints. The proposal would yield a revenue of Rs. 9 crores.

156. Currently special excise duty at the rate of 1/20th of the basic duty of excise is being levied on indigenously produced goods. However, for the computation of countervailing duty of customs on imported goods, special excise duty is not taken into account. I do not think such a distinction is warranted. I propose to subject the imported goods to countervailing duty on the basis of the excise duty inclusive of special excise duty. This proposal is expected to yield customs revenue of Rs. 60 crores.

157. The Baggage Rules relating to free allowance admissible to passengers arriving from foreign countries are being modified. The general free allowance is being increased from the existing level of Rs. 1250 to Rs. 2000 per passenger. There will be a uniform duty rate of 250 per cent for baggage in excess of this limit as against the existing 175 per cent and 245 per cent. I also propose to prescribe a uniform duty rate of 25 per cent on specified articles brought by passengers coming from abroad after a period of stay of more than year, subject to certain conditions. The revised measures will take effect from the 1st April, 1990.

158. Provision is being made for continuance of auxiliary duty of customs and special excise duty at the existing rates.

159. As the Honourable Members are aware, Inland Air Travel Tax was introduced in the Budget of last year. The tax is leviable at 10 per cent of one component of the total air fare, namely, basic fare. I propose to levy the tax at the existing rate on the full air fare. The estimated revenue gain from the proposal will be Rs. 15 crores.

160. As I mentioned in the earlier part of my speech, in recent years our consumption of petroleum products has risen sharply. Honourable Members are also aware that petroleum prices abroad have been hardening. The greater dependence on imports has led to a large outflow of foreign exchange and higher overall foreign borrowing. It has now become necessary to review the domestic prices of petroleum products. Keeping in view the interests of the common man, there will be no increase. I repeat, no increase in prices of kerosene and LPG cylinders. There will also be no increase in prices of naphtha for fertilizers and other uses, natural gas, furnace oil for industry, bitumen for roads and low speed diesel oil for farmers. Among the selected items whose prices are being revised with effect from this midnight are motor spirit, high speed diesel oil and aviation turbine fuel for domestic users. While the price of motor spirit is being raised by Rs. 1.25 per litre ex-storage, the price of high speed diesel oil will go up by 54 paise per litre. The price of aviation turbine fuel will increase by Rs. 1320.45 per kilolitre. The increase in retail prices will vary from State to State depending on transportation charges and the incidence of local taxes and levies. I propose to mop up a part of the gain accruing to the oil companies as a result of price revision. The import duty on crude oil is being increased from Rs. 1060 to Rs. 1500 per tonne. This will yield a revenue of Rs. 836 crores.

161. The government is compelled to perform this painful duty of increasing the prices of some petroleum products. But these are the hard options forced on us by the grave fiscal situation, rising external debts, and the difficult balance of payments position. We could have postponed these options only at the peril of our economic independence and self-reliance.

162. I have also proposed certain amendments in the Finance Bill seeking to effect changes in the excise and customs tariffs. These amendments are generally enabling provisions and have no revenue significance. Besides, there are proposals for amendment of some of the existing notifications. In order to save the time of the House, I do not propose to recount them.

163. The proposals in regard to changes in the excise duties outlined above are likely to yield additional revenue of Rs. 778.63 crores. The concessions and reliefs announced aggregate to Rs. 388.44 crores. Out of the net additional shareable revenue from excise duties of Rs. 390.19 crores, the centre's share would be Rs. 217.12 crores and the States share is Rs. 173.07 crores.

164. My tax effort in respect of customs duties will bring in Rs. 979.79 crores. Net of reliefs amounting to Rs. 144.76 crores, the additional revenue from customs duties accruing to the Centre will be Rs. 835.03 crores. Besides, the changes in the Inland Air Travel Tax would yield Rs. 15 crores.

165. Copies of notifications giving effect to the changes in customs and excise duties effective from the 20th March, 1990 will be laid down the Table of the House in due course.

166. I now have something to say on behalf of my Honourable colleague, the Minister of Communications. Postal Service is highly employment intensive and salary and allowances constitute a major part of the operating expenses of the Postal Department. The grant of additional instalments of Dearness Allowance and increases in other operational expenses add significantly to these costs. The postal rates do not meet even the direct cost of most of the services. A revision of tariff for some postal services has, therefore, become unavoidable. However, in the interest of the common man and cheap and wider dissemination of information, there will be no change in the tariff for ordinary postcards and registered newspapers. The rate of printed postcard, which is used mainly for business purposes, is being raised from 40 paise to 60 paise, of inland letter card from 50 paise, inclusive of the stationery charges, to a consolidated amount of 75 paise, and of envelopes to a uniform rate of Re. one for every 20 grams without any stationery charge. There are also certain other changes which are explained in the memorandum circulated alongwith the Budget documents. The changes would take effect from a date to be notified after the Finance Bill is passed. The revisions proposed are estimated to yield an additional revenue of about Rs. 207 crores in a full year and about Rs. 172 crores in 1990-91.

167. Honourable Members will recall that the 46th Constitution Amendment Act, 1982 gave enabling powers to the Parliament to levy a tax on consignment of goods where such consignment takes place in the course of inter-state trade or commerce. However, there have been differences of opinion on the modalities of implementation of this law and the matter has been discussed in various meetings of the Chief Ministers. The broad parameters have now been settled and a Committee of Chief Ministers was appointed to work out the guidelines for granting exemptions from this tax, both by the Centre and the States. I propose to consult the Chief Ministers shortly to take a final view in the matter.

168. I had earlier mentioned that the budget deficit at the existing rates of taxes would be Rs. 9165 crores. Taking into account the net additional yield from the modifications proposed in direct and indirect taxes and the revised postal tariff, the deficit for the next year is estimated at Rs. 7206 crores. Honourable Members will note that this deficit is substantially lower than the deficit of Rs. 11750 crores in the revised estimates of 1989-90. In order to give the right signal and contain inflationary pressure, I have also tried to keep next year's deficit even lower than the budget estimate of Rs. 7337 crores for the current year.

169. It is my firm determination that the deficit provided for in the budget should not be exceeded. A half-yearly review of the actual developments in the budgetary situation will be made, and the people and the Parliament kept informed about the performance in relation to the deficit.

170. We need to make our fiscal and tax system more stable and predictable. The system of making a large number of changes in the tax rates and tax laws every year, apart from introducing uncertainty, casts a severe burden on the administrative system. It also affects compliance and increases litigation. While some changes in tax rates and laws are inevitable, it is desirable to keep the basic structure stable at least for some time. With this end in view, the Government will present a document on the Long Term Fiscal Policy to Parliament.

171. With this, I have come to the end of my labours. We faced a fiscal situation which constituted a threat to the economic strength and stability of our country. The choice before us was to let things drift, borrow more and consume more or to take the corrective action now, however, difficult. We have made our choice. We have taken some resources from the rich and used them to give some relief to the poor and the common man. We have begun a process to restrain the budgetary deficit and contain the inflationary pressure. We have tilted the balance of planning and investment towards the rural areas and in favour of employment.

172. As a man of science, wedded to non-doctrinaire socialism, I consider experimentation and its results the touchstone on which can be tested the relevance of all social and economic perceptions and policies.

173. This is the essence of pragmatism and the quintessence of the unending quest of socio-economic experimenters like Gandhiji, Jyoti Basu and Acharya Narendra Dev.

174. Mr. Speaker, with my irrevocable commitment to such a pragmatic approach, I present this Budget to this august House as a short term device to move steadily, and yet resolutely, towards the long term objective of ensuring growth with equity and self-reliance. In this endeavour, I seek the wholehearted support of the people through their chosen democratic instrument this honourable Parliament.

175. Sir, I commend the Budget to the House.

Smt. JANAKI KATHPALIA, Jt. Secy. (Budget)

